हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 342 बेमेतरा, शनिवार 08 अगस्त 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने का रास्ता साफ, केंद्र सरकार को मिला अधिकार

नई दिल्ली। लोकसभा ने गुरुवार को 'कर एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के माध्यम से 'भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद केंद्र सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वह बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को यूपीआई सहित अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों पर शुल्क लगाने की अनुमति दे सके। यह विधेयक लोकसभा में बिना विस्तृत चर्चा के हंगामे के बीच ध्वनि मत से पारित किया गया। दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे विचार और पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखा। अब तक लागू भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10-ए के तहत बैंकों और डिजिटल भुगतान मंचों को ग्राहकों या व्यापारियों से किसी भी प्रकार का शुल्क लेना प्रतिबंधित था।

कम्प्रेस्ड बायोगैस के लिए राष्ट्रीय एकीकृत योजना गोबरधन को मिली मंजूरी

नई दिल्ली। कैबिनेट ने गुरुवार को देश में बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से 23,731 करोड़ रुपये की लागत वाली एक एकीकृत सर्कुलर बायो-एनर्जी योजना को मंजूरी दी.सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ब्रीफिंग में कहा कि गोवर्धन योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी और यह कंप्रेस्ड बायोगैस को भारत के भविष्य के एनर्जी मिक्स का एक अहम हिस्सा बनाएगी. एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस योजना का मकसद देश में बड़ी मात्रा में मौजूद कृषि अवशेषों, पशुओं के गोबर, प्रेस मड, नगरपालिका के जैविक कचरे और अन्य बायोमास संसाधनों को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद, ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में बदलना है. इसमें आगे कहा गया कि पक्की मांग, अच्छी और स्थिर कीमतों, पूंजीगत सहायता, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट सपोर्ट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के जरिए।

सरकार ने मेटो को साफ-साफ बताया, हर हाल में करना पड़ेगा कानून का पालन

नई दिल्ली। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने मेटा की उस टीम से सवाल किया, जो भारत आई है. पूछताछ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगाने के मामले में सोशल मीडिया कंपनी को समन भेजे जाने के बाद की गई. सरकार और मेटा की ग्लोबल टीम के बीच बातचीत संपन्न हो गई है. सरकारी सूत्रों ने बताया कि मेटा से उनके एल्गोरिदम के बारे में भी सवाल किए गए. उनसे यह पूछा गया कि क्या उनके नियमों का पालन करने वाले सिस्टम में संवैधानिक और कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जांच-पड़ताल और सुरक्षा उपाय मौजूद हैं.

नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई चार्जशीट में बड़ा खुलासा

एनटीए एक्सपर्ट्स ने याद कर बाहर पहुंचाए सवाल

नई दिल्ली/ एजेंसी

सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में दाखिल चार्जशीट में कई डिजिटल और फोरेंसिक सबूतों का जिक्र किया है। इनमें पुणे की एक रिहायशी सोसायटी के एंट्री मैनेजमेंट एप का रिकॉर्ड भी शामिल है। इसी सोसायटी में एनटीए के केमिस्ट्री विषय के विशेषज्ञ और आरोपी पीवी कुलकर्णी रहते थे। सीबीआई ने 28 जुलाई को विशेष अदालत में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अधिकारियों के मुताबिक, सोसायटी के एप से मिले रिकॉर्ड में उन छात्रों की बायोमेट्रिक एंट्री भी शामिल है, जो कुलकर्णी की ओर से अप्रैल में आयोजित विशेष कोचिंग कक्षाओं में आते थे। सीबीआई ने एप के रिकॉर्ड के जरिए छात्रों और उनके अभिभावकों की सोसाइटी में मौजूदगी की पुष्टि की। ये लोग नीट यूजी परीक्षा से कुछ दिन पहले अप्रैल में कुलकर्णी की सोसाइटी में आए थे। एजेंसी ने इन रिकॉर्ड को छात्रों के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन विश्लेषण से भी मिलाया। नीट यूजी परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी। सीबीआई की जांच में एनटीए के पैनल में शामिल पुणे के तीन विषय विशेषज्ञों की भूमिका सामने आई। इनमें शामिल हैं: पीवी कुलकर्णी, केमिस्ट्री मनीषा गुरुनाथ मंधारे, जूलॉजी और बॉटनी मनीषा संजय हवलदार, फिजिक्स एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर

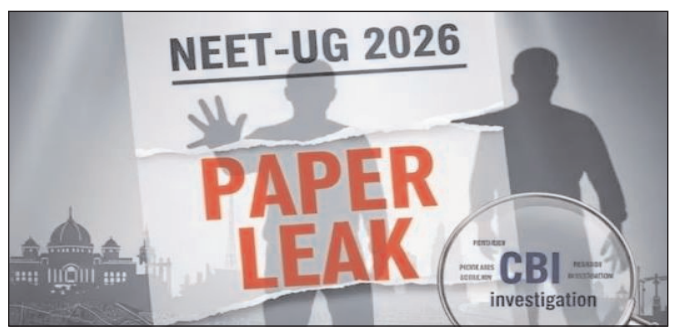

गोपनीय सवाल हासिल किए और उन्हें पैसे लेकर आगे पहुंचाया। सीबीआई के अनुसार, ब्यूटीशियन मनीषा संजय वाघमारे ने कुलकर्णी और मंधारे की अप्रैल में हुई विशेष कोचिंग कक्षाओं में छात्रों को भेजा था। वहां छात्रों की कॉपियों में विशेषज्ञों की ओर से बताए गए सवाल लिखे गए थे। कुछ सवालों को 'महत्वपूर्ण' और 'बहुत महत्वपूर्ण' के तौर पर चिह्नित किया गया था। एजेंसी के मुताबिक, यही सामग्री बाद में राजस्थान और हरियाणा तक छात्रों और बिचौलियों की एक श्रृंखला के जरिए पहुंचाई गई। सीबीआई ने हवलदार की भूमिका का भी जिक्र किया है। आरोप है कि मंधारे के कहने पर उन्होंने एक अभ्यर्थी की मां को फिजिक्स के 68 सवालों वाले 16 पन्ने उपलब्ध कराए। जांच एजेंसी ने अलग-अलग छात्रों और बिचौलियों से मिले लीक प्रश्नों और अन्य सामग्री को दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से गठित विशेषज्ञ पैनल को भेजा। जांच में इस सामग्री का नीट यूजी 2026 के चार पेपर सेट से अलग-अलग स्तर पर मिलान पाया गया। सीबीआई के अनुसार, जिन सेट तक संबंधित विशेषज्ञों की पहुंच थी, उनमें सवालों का मिलान 85 फीसदी तक पाया गया। जिन सेट तक उनकी पहुंच नहीं थी, उनमें मिलान काफी कम था। सीबीआई के अनुसार, नीट के प्रश्नपत्रों की तैयारी, अनुवाद और बैक-ट्रांसलेशन का काम एनटीए के ओखला स्थित भवन में नियंत्रित माहौल में किया गया था।

पेपर लीक करवाना मर्डर से भी जघन्य अपराध, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक करवाना हत्या के अपराध से भी अधिक जघन्य है। यह लाखों उम्मीदवारों के करियर को बर्बाद कर देता है और समाज पर बुरा असर डालता है। 62 साल के आरोपी जीवन किशोर ध्रुव को सीबीआई ने सितंबर 2025 में गिरफ्तार किया था। वह 2020-2022 भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के समय सीजीपीएससी के सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। जीवन किशोर के बेटे सुमित ध्रुव भी इस मामले में आरोपी हैं। वह भर्ती परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के तौर पर चुने गए थे। जस्टिस बिभू दत्ता गुरु ने 31 जुलाई को जीवन किशोर ध्रुव की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया। हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए इस मामले में दूसरे आरोपियों की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते समय की गई अपनी पिछली बातों को दोहराया।

बेरोजगारों की आवाज बनेगी सीजेपी

दीपके बोले छात्रों को मिला हक अब युवाओं की बारी

मुंबई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की कोर टीम की बैठक के बाद संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी अब केवल युवाओं की व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। उन्होंने घोषणा की कि सीजेपी आने वाले समय में बेरोजगारी के मुद्दे को देशव्यापी जनआंदोलन का रूप देने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी। उनका कहना है कि युवाओं को रोजगार के सवाल पर संगठित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभिजीत दिपके ने कहा कि हाल ही में जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध

प्रदर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया कि रोजगार का मुद्दा केवल छात्रों तक सीमित नहीं है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने भी भाग लिया, जिससे यह साबित हुआ कि रोजगार की समस्या समाज के हर वर्ग के युवाओं को प्रभावित कर रही है।

रांची छात्र आंदोलन में नेहा बोरा ने दिया समर्थन

विधानसभा घेराव के दौरान एआईएसए अध्यक्ष नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही,पेलेट गन से नहीं डरे.....

रांची। राजधानी रांची में छात्र आंदोलन के बीच शुक्रवार को बड़ा हंगामा हो गया। विधानसभा घेराव के दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक छात्र ने स्याही फेंक दी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल आरोपी छात्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इससे पहले नेहा बोरा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर जेपीएससी-जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की और उनके आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। नेहा बोरा ने कहा कि छात्रों की मांगें पूरी तरह जायज हैं और सरकार को उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठा रहे हैं, इसलिए उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार यह केवल छात्रों का नहीं, बल्कि राज्य के युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। धरना स्थल पर विधानसभा घेराव को लेकर भी

चर्चा हुई। नेहा बोरा ने छात्रों से समर्थन की अपील की, लेकिन आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन पूरी तरह गैर-राजनीतिक है और वे किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। नेहा बोरा ने अनशन पर बैठे छात्र देवेंद्र महतो से भी मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। छात्रों ने बताया कि उनका अपना विधानसभा घेराव कार्यक्रम 10 अगस्त को निर्धारित है और उसी के माध्यम से वे अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखेंगे।इसके बाद नेहा बोरा अपने संगठन के साथ विधानसभा घेराव के लिए रवाना हो गईं। नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि जो लोग खुद को छात्रों का हितैषी बताते हैं, वही छात्र आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर निकाले गए विधानसभा मार्च के दौरान उन पर स्याही फेंकी गई। उनका आरोप है कि इस तरह की कार्रवाई छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश है।

---

7 साल की उम्र में छोड़ा था भारत

आभा नायर बनीं जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

दिल्ली में जन्मीं और जाम्बिया में पली-बढ़ीं जस्टिस आभा नायर पटेल ने न्यायिक इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है। वह जाम्बिया के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बन गई हैं। इसके साथ ही, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के विशेष आमंत्रण पर भारत के सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पीठ पर बैठने वाली जाम्बिया की पहली जज बनने का गौरव भी उन्होंने हासिल किया। वर्ष 1973 में, जब आभा नायर मात्र सात वर्ष की थीं, तब उनके माता-पिता बेहतर आजीविका की

तलाश में दिल्ली से जाम्बिया चले गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जाम्बिया से कानून की पढ़ाई की और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी (ब्रिटेन) से मास्टर डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1989 में जाम्बिया बार में शामिल होने के बाद उन्होंने अपनी ईमानदारी, मेहनत और पेशेवर उत्कृष्टता के दम पर अलग पहचान बनाई। आभा नायर पटेल को वर्ष 2019 में हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अप्रैल 2023 में उन्हें कोर्ट ऑफ अपील में पदोन्नति मिली और 27 मई 2026 को उन्होंने जाम्बिया के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया। न्यायिक उपलब्धियों के अलावा वह एक पर्वतारोही भी हैं और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलता पूर्वक चढ़ाई कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन के कार्यक्रम में जस्टिस पटेल ने कहा कि प्रभावी न्याय प्रणाली के तीन आधार हैं।

1 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बरामद

नई दिल्ली। नॉर्थ-ईस्ट जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने अवैध रूप से प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट की सप्लाई करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 2,82,640 प्रतिबंधित आयातित सिगरेट बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है. मामले में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है. डीसीपी राहुल अलवाल ने जानकारी दी कि 4 अगस्त 2026 को स्पेशल स्टाफ के एसआई कौशिक घोष को सूचना मिली थी कि करावल नगर क्षेत्र में प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट की खेप पहुंचाई जाने वाली है.

ममता और उद्धव के बागी सांसदों संग ब्रेकफास्ट मीटिंग

बागी सांसदों से बोले पीएम मोदी चिंता मत करो,मैं आपके साथ हूं

नई दिल्ली/ एजेंसी

ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले सांसदों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रेकफास्ट मीटिंग की। आज (7 अगस्त) सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे गुट से अलग हुए सांसदों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। प्रधानमंत्री मोदी से सभी बागी सांसदों से अपने-अपने क्षेत्र में विकास पर ध्यान देने की बात करते हुए कहा कि अगर विकास परियोजनाओं से जुड़ी किसी भी

तरह की समस्या आती है, तो वे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करें। बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी बागी सांसदों से संसद की डिबेट में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए एक परिवार है। उन्होंने शिवसेना में हाल ही में शामिल 6 सांसदों के साथ एक अलग बैठक की। उन्होंने सांसदों से संसदीय इतिहास को पढ़ने, जानने और समझने के लिए कहा। पीएम मोदी ने बताया कि संसद में इतिहास से जुड़ा बहुत सारा मैटेरियल उपलब्ध है, डिबेट में तैयारी करने के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए। साथ ही सांसदों को अपने-अपने राज्यों के विकास के लिए काम करने की सलाह दी और इस बात पर जोर दिया कि जब राज्य आगे बढ़ेंगे, तभी देश का भी विकास होगा। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने धाराशिव से सांसद ओमराजे निंबालकर से उनके योग अभ्यास के बारे में भी पूछा।

क्या है 10 से 12 अगस्त का प्लान?

संसद में घमासान के आसार-कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया व्हिप

नई दिल्ली/ एजेंसी

संसद के मानसून सत्र के बीच राजनीतिक सरगर्मियां अचानक तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में अपने सभी सांसदों को उपस्थित रहने का फरमान जारी किया है। पार्टी ने राज्यसभा और लोकसभा के अपने सदस्यों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। इसके तहत सभी सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। पार्टी के अनुसार इन तीन दिनों में बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को भी एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने 'इंडिया गठबंधन' के सभी साथी दलों से भी संपर्क किया है। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इन तीन दिनों के दौरान अपने सांसदों की सौ फीसदी मौजूदगी सुनिश्चित करें। पिछले दिनों संसद की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे हमलावर दिखे थे। उन्होंने छात्र आंदोलन पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब विवादास्पद एफसीआरए संशोधन विधेयक पर चर्चा की खबरें आ रही हैं। माना जा रहा है कि सरकार अगले हफ्ते इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए ला सकती है। इसके साथ ही परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि, संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने अगले हफ्ते के संभावित सरकारी कामकाज का ब्योरा देते समय स्थिति साफनहीं की। उन्होंने अपने बयान

में एफसीआरए संशोधन विधेयक या महिला आरक्षण व परिसीमन से जुड़े विधेयक का कोई जिक्र नहीं किया। इसके बावजूद विपक्ष कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने तीन लाइन का व्हिप जारी करते हुए कहा, 'सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी 10, 11 और 12 अगस्त 2026 को राज्यसभा में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।' उन्होंने निर्देश दिया, 'कांग्रेस के सभी राज्यसभा सदस्य 10, 11 और 12 अगस्त को सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही स्थगित होने तक अनिवार्य रूप से मौजूद रहें। सभी सदस्य पार्टी के रुख का समर्थन करें। इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाए।' ऐसा ही व्हिप लोकसभा में भी कांग्रेस सदस्यों के लिए जारी किया गया है। क्या हैं इस घटनाक्रम के पांच मुख्य बिंदु? कड़ा फरमान: कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का सख्त व्हिप जारी किया। अनिवार्य उपस्थिति: 10, 11 और 12 अगस्त को सुबह 11 बजे से सदन स्थगित होने तक रहना होगा। विपक्षी एकजुटता: 'इंडिया' गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से भी सांसदों की उपस्थिति पक्की करने को कहा। संभावित बिल: एफसीआरए संशोधन बिल और परिसीमन से जुड़े विधेयक पर चर्चा की संभावना। पार्टी का निर्देश: सभी सांसदों को बिना चुके सदन में उपस्थित रहकर पार्टी के रुख का समर्थन करने का आदेश।

विरोधी हैं दुश्मन नहीं- राहुल गांधी से मिले किरेन रिजिजू,क्या थमेगा संसद का घमासान?

भारतीय राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अक्सर तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद रिजिजू का एक बयान सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम राजनीतिक विरोधी जरूर हैं, लेकिन दुश्मन नहीं। दिल्ली में हुई इस मुलाकात को किरेन रिजिजू ने काफी सकारात्मक बताया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने साझा किया कि राहुल गांधी के साथ उनकी चर्चा काफी अच्छी रही।

कांकेर में भालू का खूनी तांडव: तीन मौतों से दहला जिला, गांव में मातम, आज भी क्षेत्र में मंडरा रहा है भालू

दैनिक मूक पत्रिका जिला बस्तर जगदलपुर से संभागीय ब्यूरो चीफपवन कुमार नाग की रिपोर्ट

मरकाटोला में भाई-बहन की दर्दनाक मौत, सिहरिनाला में बुजुर्ग की भी गई जान; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, ग्रामीणों में दहशत बरकरार

कांकेर /मूक पत्रिका

कांकेर जिले के नरहरपुर वन परिक्षेत्र में भालू के खूनी हमलों ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। मंगलवार को हुई दो अलग-अलग घटनाओं में तीन ग्रामीणों की दर्दनाक मौत और एक महिला के गंभीर रूप से घायल होने के बाद मरकाटोला और सिहरिनाला गांवों में मातम पसरा हुआ है। मृतकों के घरों में चीख-पुकार और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव का माहौल गमगीन है और लोगों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा हैं। मूक पत्रिका संवाददाता को ग्रामीणों ने बताया कि मरकाटोला गांव में अपने मृत शावक के कारण आक्रामक हुई मादा भालू ने खेत में काम कर रहे हलालखोर जुरी (45) और उनकी बहन चमरिन जुरी (40) पर अचानक हमला कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें बचाने पहुंची सौरिन जुरी (30) भी भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है।इसी दिन नरहरपुर थाना क्षेत्र के सिहरिनाला गांव में 67 वर्षीय देवबली ध्रुवा भी भालू के हमले का शिकार हो गए। देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश की तो उनका शव खेत के पास मिला। लगातार हुई इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया है।सबसे दर्दनाक दृश्य मरकाटोला में देखने को मिला, जहां मादा भालू करीब पांच घंटे तक मृतकों के शवों के पास डटी रही। वन विभाग और पुलिस की टीम भी तत्काल शवों तक नहीं पहुंच सकी। बाद में रायपुर से पहुंची विशेष रेस्क्यू टीम ने ट्रैंक्विलाइजर गन की मदद से मादा भालू को बेहोश कर काबू में लिया, जिसके बाद।

ग्राम बड़े घोटला में स्व. देवनारायण पटेल एवं स्व. सविता पटेल का दशगात्र संपन्न

जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और हजारों लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

ग्राम बड़े घोटला में पूर्व सरपंच स्व. देवनारायण पटेल एवं उनकी धर्मपत्नी स्व. सविता पटेल के दशगात्र एवं गंगाभोज कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, समाजसेवियों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शामिल होकर दिवंगत दंपति को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई, पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा, जिला पंचायत सीईओ ऋषिकेश तिवारी, एसडीएम, जनपद सीईओ सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगतों के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। जिलाअध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ताराचंद देवांगन ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि इस कठिन समय में पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा है। वहीं चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव ने इसे क्षेत्र के लिए अत्यंत दुखद घटना बताते हुए दिवंगत दंपति के सामाजिक योगदान को याद किया।पूर्व संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने कहा कि स्व. देवनारायण पटेल एवं स्व. सविता पटेल का असमय निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि घनश्याम मनहर, सूरज तिवारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पदाधिकारी, समाजसेवी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।

देश की सुरक्षा पर डटे जवानों तक पहुंचेगा बहनों का स्नेह, स्कूली छात्राओं ने कलेक्टर को सौंपे रक्षासूत्र

बलौदाबाजार/मूक पत्रिका

ताराचंद कठोत्रे /रक्षाबंधन के पावन अवसर को विशेष रूप देने और देश की रक्षा के लिये सीमाओं पर तैनात वीर जवानों तक बहन के स्नेह का प्रतीक पहुंचाने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल की गई। गुरुकुल हायर सेकेण्डरी स्कूल बलौदाबाजार एवं शास्वत हाई स्कूल बलौदाबाजार की छात्राओं द्वारा बनाए गए रक्षासूत्रों को कलेक्टर कुलदीप शर्मा को सौंपा।कलेक्टर श्री शर्मा ने छात्राओं को इस पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह कार्य न केवल रक्षाबंधन पर्व को एक नया स्वरूप प्रदान करता है बल्कि देशभक्ति और नागरिक जिम्मेदारी की अद्भुत मिसाल भी पेश करता है। उन्होंने कहा कि हमारे वीर जवान अपनी जान की परवाह किए बिना सीमाओं पर डटे रहते हैं।

जगन्नाथ मंदिर में गूंजा महामृत्युंजय मंत्र, किरण सिंह देव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना

कुमार जयदेव बाबा एवं जिला पंचायत सदस्य शंकुतला कश्यप हुए शामिल, श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से किया मंत्र जाप

जगदलपुर/मूक पत्रिका

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ, दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना को लेकर जगदलपुर स्थित महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं एवं कार्यकर्ताओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर महामृत्युंजय मंत्र का सामूहिक जाप किया। मंदिर परिसर में मंत्रोच्चार से भक्तिमय वातावरण निर्मित हो गया।आयोजन में सुकमा जमींदार कुमार जयदेव बाबा एवं जिला पंचायत सदस्य शंकुतला कश्यप विशेष रूप से शामिल हुए। दोनों ने भगवान जगन्नाथ की पूजा-अर्चना कर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई। धार्मिक आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं माता सुभद्रा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर पूजा-अर्चना की। इसके बाद पंडितों एवं उपस्थित श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। मंत्र जाप के दौरान मंदिर परिसर में आध्यात्मिक एवं श्रद्धामय माहौल बना रहा। उपस्थित लोगों ने एक स्वर में भगवान महादेव से किरण सिंह देव के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। कुमार जयदेव बाबा ने कहा कि धार्मिक आस्था और सामूहिक प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। भगवान जगन्नाथ एवं महादेव से प्रार्थना है कि किरण सिंह देव को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले और वे पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर पुनः जनसेवा में सक्रिय हों। उन्होंने कहा कि उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु के लिए निरंतर प्रार्थना की जा रही है।जिला पंचायत सदस्य शंकुतला कश्यप ने कहा कि किरण सिंह देव बस्तर के विकास और जनहित के लिए निरंतर सक्रिय रहने वाले जनप्रतिनिधि हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में प्रार्थना की गई है। उन्होंने कहा कि सभी की सामूहिक प्रार्थना और भगवान का आशीर्वाद निश्चित रूप से उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की शक्ति प्रदान करेगा।आयोजन में शामिल लोगों ने कहा कि किरण सिंह देव के प्रति बस्तरवासियों की आत्मीयता और शुभकामनाएं लगातार बनी हुई हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर लोगों में चिंता के साथ-साथ शीघ्र स्वस्थ होने की प्रबल कामना है। इसी भावना के साथ धार्मिक स्थलों में पूजा-पाठ, मंत्र जाप और प्रार्थना का सिलसिला जारी है।महामृत्युंजय मंत्र जाप के समापन पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ से किरण सिंह देव के शीघ्र स्वस्थ होने, दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। धार्मिक आयोजन के माध्यम से लोगों ने एकजुट होकर अपनी आस्था और शुभेच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर कुमार जयदेव बाबा, जिला पंचायत सदस्य शंकुतला कश्यप सहित भाजपा कार्यकर्ता, श्रद्धालु एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

शासकीय पॉलिटेक्निक थानखम्हरिया में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश का चौथा चरण प्रारंभ

बेमेतरा ।तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक थानखम्हरिया, जिला बेमेतरा में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश का सुनहरा अवसर उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एवं केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान में प्रारंभ हो चुकी है। संस्था के प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत 10वीं उत्तीर्ण (पी.पी.टी. के माध्यम से), आईटीआई उत्तीर्ण तथा 12वीं (गणित विषय सहित) उत्तीर्ण अभ्यर्थी निर्धारित नियमों के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र हैं।

धरमजयगढ़ एकलव्य विद्यालय में भड़का छात्रों का आक्रोश, बदहाली से तंग आकर कक्षाओं का किया बहिष्कार, प्राचार्य पर लगे गंभीर आरोप

रायगढ/मूक पत्रिका

जिले के धरमजयगढ़ स्थित संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (हीरापुर, लैलूंगा) में गुरुवार को अव्यवस्थाओं का घड़ा फूट पड़ा। विद्यालय प्रशासन और प्राचार्य के रवैये से परेशान होकर छात्र-छात्राओं ने कक्षाओं का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया और परिसर में उग्र प्रदर्शन किया।छात्रों का आरोप है कि उन्हें परोसे जाने वाले भोजन में आए दिन कीड़े और कांच के टुकड़े मिलते हैं। छात्राओं ने बताया कि गर्ल्स वॉशरूम इतने गंदे और बदबूदार रहते हैं कि उनका उपयोग करना मुश्किल हो गया है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के पास पढ़ने के लिए किताबें तक उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स का सामान, टूर, वार्षिक उत्सव (एनुअल फंक्शन) और यूनिफॉर्म जैसी बुनियादी चीजें भी बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं।विद्यार्थियों ने सीधे प्राचार्य पर निशाना साधते हुए उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि प्राचार्य महीने-सप्ताह में एकाध दिन ही विद्यालय आते हैं। जब भी लिखित में समस्याएं दी जाती हैं, तो ष्ऊपर भेज रहे हैंष् कहकर टाल दिया जाता है।जब इस संबंध में प्रभारी प्राचार्य से सवाल किए गए, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि विद्यालय में 4-4 हॉस्टल के बच्चे रहते हैं, इसलिए कभी-कभी थोड़ी बहुत भूल-चूक हो जाती है। रायगढ़ एससी ऑफिस के शासकीय कार्यों से बाहर रहने के कारण वे नियमित नहीं आ पाते। भोजन में कांच मिलने की बात पर उन्होंने माना कि बहुत पहले ऐसी घटना हुई थी, जिसके बाद रसोइयों को सतर्क किया गया था।

वहीं छात्रों का कहना है कि समस्या जस की तस बनी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आदिवासी व मेधावी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा देने के उद्देश्य से भारी-भरकम फंड दिया जाता है। इसके बावजूद विद्यालय में किताबों, खेल सामग्री और सुरक्षित भोजन के लिए तरसते बच्चे प्रशासनिक व्यवस्था की नाकामी को बयां कर रहे हैं। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक प्राचार्य पर कार्रवाई और व्यवस्था में सुधार नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

रायगढ़ में 550 नवनिर्वाचित सरपंचों को मिल रहा हाईटेक प्रशिक्षण: GIS और पीएम गतिशक्ति से तैयार होगा गांवों के विकास का रोडमैप

रायगढ/मूक पत्रिका

ग्रामीण विकास की अवधारणा को धरातल पर मजबूत करने और पंचायती राज व्यवस्था को आधुनिक तकनीकों से लैस करने के उद्देश्य से जिला पंचायत रायगढ़ द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। जिले के सचिव प्रशिक्षण संस्थान (टी.वी. टॉवर रोड, रायगढ़) में 3 से 10 अगस्त तक नवनिर्वाचित सरपंचों के लिए विशेष क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस चरणबद्ध प्रशिक्षण में जिले की विभिन्न जनपद पंचायतों के लगभग 550 सरपंच भाग ले रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से आयोजित हो रहे इस सत्र में सरपंचों को पार पारंपरिक तरीकों से हटकर वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित ग्राम विकास योजनाएं बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य 'विकसित भारत 2047' की परिकल्पना के तहत गांवों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सतत विकास की ओर अग्रसर करना है। यह प्रशिक्षण अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीला राम पटेल के मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है। सत्रों के दौरान सहायक परियोजना अधिकारी श्री ऋषि गणेशन नायक, तकनीकी समन्वयक श्री आशुतोष श्रीवास्तव एवं जिला प्रोग्रामर श्री अभिषेक दांडेकर द्वारा व्यावहारिक उदाहरणों और तकनीकी प्रेजेंटेशन के जरिए सरपंचों को वीबी-जीराम जी योजना, जीआईएस आधारित प्लानिंग, पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म, रिसोर्स मैपिंग और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की बारीकियों से रूबरू कराया जा रहा है।प्रशिक्षण के दौरान विकसित भारत जी-राम योजना के चार मुख्य स्तंभों–जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, ग्रामीण आजीविका और आपदा न्यूनीकरण पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही भू-जल पुनर्भरण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वाटरशेड विकास और वनीकरण के माध्यम से स्थायी जनहितकारी परिसंपत्तियों के निर्माण की रणनीतियां सिखाई जा रही हैं।प्रशिक्षण सत्र में 125 दिनों की रोजगार गारंटी, विभागीय अभिसरण और पंचायत सशक्तिकरण पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि योजना का उद्देश्य केवल भौतिक निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि पंचायतों में महिला सहभागिता, पारदर्शी प्रशासन और आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देना है।

कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने प्राचार्यों से किया सीधा संवाद, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए साझा किया विजन

मिशन आचार्य से बदलेगी जिले की शिक्षा व्यवस्था, हर विद्यालय बनेगा उत्कृष्टता का केंद्र

बलरामपुर/मूक पत्रिका

जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई दिशा देने और प्रत्येक विद्यालय को उत्कृष्टता का केंद्र बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने 'मिशन आचार्य' की नवाचारी पहल शुरू की है। इसी कड़ी में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी की अध्यक्षता तथा जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी की उपस्थिति में जिले के प्राचार्यों का प्रशिक्षण सह कार्यशाला एवं संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया।

कार्यशाला में कलेक्टर ने प्राचार्यों से सीधे संवाद करते हुए मिशन आचार्य की कार्ययोजना, विजन, रणनीति और उत्तरदायित्व आधारित कार्यप्रणाली की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि एक अच्छा विद्यालय केवल भवन से नहीं, बल्कि सक्षम प्राचार्य, प्रेरित शिक्षक और सीखने के उत्साह से भरे बच्चों से बनता है। मिशन आचार्य का उद्देश्य केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें जीवन के लिए तैयार करना है।

हर बच्चे के सीखने के स्तर पर होगी नजर-कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि आज आवश्यकता केवल विद्यालयों के संचालन की नहीं, बल्कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करने की है, जहां हर बच्चा अपनी कक्षा के अनुरूप सीख सके, हर शिक्षक निरंतर सीखता रहे और हर विद्यालय उत्कृष्टता का केंद्र बने। मिशन की सफलता बैठकों और गतिविधियों की संख्या से नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सीखने के स्तर और विद्यालयों के प्रदर्शन से मापी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर विद्यालयों की नियमित समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता के अनुसार समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। नवाचारों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने प्राचार्यों से कहा कि बचपन जीवन का ऐसा पड़ाव है, जो दोबारा लौटकर नहीं आता। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता और आवश्यकता को समझकर उसे उचित मार्गदर्शन देना शिक्षक और प्राचार्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

प्राचार्य के नेतृत्व से तय होता है विद्यालय का भविष्य-जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि विद्यालय का भविष्य प्राचार्य के नेतृत्व से तय होता है। यदि प्राचार्य स्वयं सीखने और बदलाव के लिए तैयार होगा तो शिक्षक भी प्रेरित होंगे और इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव बच्चों के सीखने पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर केवल परीक्षा परिणामों से नहीं बढ़ता, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नियमित शैक्षणिक समीक्षा, नवाचार, शिक्षक मार्गदर्शन और सकारात्मक सीखने के वातावरण से बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा शिक्षक कक्षा बदल सकता है, लेकिन एक अच्छा प्राचार्य पूरे विद्यालय की तस्वीर बदल सकता है।

मिशन आचार्य के पांच प्रमुख स्तंभ-कार्यशाला में मिशन आचार्य के पांच प्रमुख स्तंभों सक्षम विद्यार्थी, सक्षम शिक्षक, सक्षम विद्यालय, सक्षम समाज एवं सक्षम प्रशासन पर विस्तार से चर्चा की गई।

साथ ही रीडिंग मिशन, होम रीडिंग कार्यक्रम, सामुदायिक पठन अभियान, रेमेडियल लर्निंग, शिक्षक क्षमता संवर्धन, एआई आधारित शिक्षण सहयोग, स्कूल परफॉर्मेंस इंडेक्स तथा रियल-टाइम जिला शिक्षा डैशबोर्ड जैसी नवाचारी पहलों का प्रस्तुतीकरण किया गया। मिशन आचार्य को शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सामाजिक जनआंदोलन के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया गया। इसमें प्रशासन के साथ शिक्षक, अभिभावक, पंचायत, जनप्रतिनिधि और समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।कार्यशाला के अंत में अधिकारियों, प्राचार्यों, बीईओ एवं बीआरसी ने मिशन आचार्य को सफल बनाने तथा बलरामपुर जिले को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श जिला बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी श्री मनीराम यादव, डीएमसी श्री चन्द्रभूषण गुप्ता सहित जिले के प्राचार्यगण उपस्थित रहे।

सारंगढ़ जिला अस्पताल में 8 अगस्त को होगा पीएम सुरक्षित मातृत्व शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिला प्रशासन सारंगढ़- बिलाईगढ़ द्वारा मातृ-शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। इसी कड़ी में हर महीने की 9 और 24 तारीख को आयोजित होने वाला 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' का शिविर इस बार 9 अगस्त को रविवार होने के कारण 8 अगस्त यानी शनिवार को जिला चिकित्सालय सारंगढ़ में आयोजित किया जाएगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य हर गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य जांच सुहैया कराना है। इस अभियान के तहत जिला चिकित्सालय में कई सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाएंगी, जिसमें ?सम्पूर्ण स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा गर्भवती महिलाओं का गहन स्वास्थ्य परीक्षण, ?निःशुल्क सोनोग्राफी, गर्भस्थ शिशु की सेहत की सटीक निगरानी के लिए हाई-टेक सोनोग्राफी की मुफ्त सुविधा, खून, पेशाब समेत अन्य जरूरी पैथोलॉजी टेस्ट शामिल है। शिविर में आने वाली सभी गर्भवती माताओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक स्वल्पाहार की विशेष व्यवस्था की गई है।

जनपद पंचायत साजा में विकसित भारत जी रामजी योजना अंतर्गत सरपंचों का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

ग्राम विकास की कार्ययोजना, जनभागीदारी और योजनाओं के अभिसरण की दी गई जानकारी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जनपद पंचायत साजा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोमनाथ साहू के मार्गदर्शन में विकसित भारत जी रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर ग्राम पंचायतों के सरपंचों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में जनपद पंचायत साजा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा योजना के विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्यों एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यक्रम अधिकारी अरविन्द कश्यप द्वारा विकसित भारत जी रामजी योजना के उद्देश्य, कार्ययोजना निर्माण, प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम स्तर पर विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने, जनभागीदारी सुनिश्चित करने तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के अभिसरण के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

उन्होंने योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। प्रशिक्षण के दौरान सरपंचों द्वारा योजना से संबंधित पूछे गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

मनरेगा के अपूर्ण कार्यों को नियमानुसार पूर्ण करने के निर्देश–प्रशिक्षण के दौरान मनरेगा अंतर्गत अपूर्ण कार्यों की भी समीक्षा की गई। सरपंचों को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों में लंबित एवं अपूर्ण कार्यों को नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराया जाए। साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई।कार्यक्रम में एसडीओ आरईएस गणेश राम मंडारे एवं तकनीकी सहायक अमित सिरेकर ने भी सरपंचों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों एवं मैदानी अमले के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।

ग्राम विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण–प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत जी रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की क्षमता का विकास करना, उन्हें योजना की प्रक्रिया एवं प्रावधानों से अवगत कराना तथा ग्राम स्तर पर योजनाओं के सफल संचालन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना था। अधिकारियों ने कहा कि ग्राम पंचायतों के विकास में सरपंचों की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्थानीय आवश्यकताओं एवं ग्रामीणों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की बेहतर कार्ययोजना तैयार करने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। प्रशिक्षण के माध्यम से सरपंचों को शासन की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, जनभागीदारी बढ़ाने तथा ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रेरित किया गया।

सारंगढ़ नगरपालिका के विकास कार्यों का कलेक्टर ने की समीक्षा

दो वर्षों से शुरू नहीं हुए कार्यों के वर्क ऑर्डर निरस्त करने के निर्देश

समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों को नोटिस

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने नगरपालिका परिषद सारंगढ़ क्षेत्र में संचालित विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों, इंजीनियरों एवं ठेकेदारों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए। ऐसे निर्माण कार्य, जिनका वर्क ऑर्डर जारी होने के बावजूद दो वर्षों से कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उनका वर्क ऑर्डर निरस्त करने कलेक्टर ने नगरपालिका सीएमओ को निर्देश दिए। कलेक्टर ने ठेकेदारों को मुड़ा तालाब में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाकर शीघ्र पूर्ण करने और निर्माणाधीन नालंदा परियोजना को दिसंबर माह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में सीसी रोड, नाली निर्माण, मुड़ा तालाब विकास कार्य, नालंदा परिसर सहित अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बरसात समाप्त होते ही सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। जिन ठेकेदारों के कार्य अभी तक अधूरे हैं, वे जल्द से जल्द गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करें। समय पर कार्य पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाए। बैठक में डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल, नगरपालिका सीएमओ, नगरपालिका के इंजीनियर, पीएचई विभाग के ईई रमाशंकर और ठेकेदारगण उपस्थित थे।

संजय पाण्डेय सहित भाजपा परिवार ने दिवंगत दंपति को दी भावभीनी श्रद्धांजलि..

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

ग्राम घौठला बड़े में दिवंगत देवनारायण पटेल एवं उनकी धर्मपत्नी सविता पटेल के दशगात्र व गंगाभोज कार्यक्रम के दौरान पूरा क्षेत्र गहरे शोक में डूब गया। इस दुखद अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा एवं शोकसभा में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण एकत्रित हुए। सभी ने दिवंगत दंपति की पुण्य स्मृति में श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में सांत्वना दी।कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय भूषण पाण्डेय ने दिवंगत आत्माओं के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए श्री पाण्डेय ने कहा, ÷इस अत्यंत कठिन और दुखद घड़ी में पूरा समाज और क्षेत्र आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।÷श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने दिवंगत दंपति की याद में दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। दोहरे शोक के कारण पूरी शोकसभा का वातावरण अत्यंत भावुक और गमगीन रहा।इस अवसर पर ज्योति पटेल, अजेश अग्रवाल, सहोदरा सिदार, अभिलाषा कैलाश नायक, हरिहर जायसवाल, जगन्नाथ केसरवानी सहित अनेक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट की।

लैलूंगा के ग्राम छापरपानी में डबल मर्डर और दुष्कर्म कांड का खुलासा, 65 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार महिला से जबरन दुष्कर्म के विरोध पर ईंट से प्राण घातक चोट पहुंचाया, 10 माह की मासूम बच्ची की भी गला घोंटकर ली थी जान

आरोपी के हाथ में चोट के निशान और अहम सबूतों से आरोपी तक पहुंची पुलिस, मनोवैज्ञानिक पूछताछ में टूटा आरोपी, हत्या-दुष्कर्म का जुर्म कबूला

एसएसपी शशि मोहन सिंह : 21 दिन में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाना टीमवर्क, धैर्य और वैज्ञानिक विवेचना का परिणाम

रायगढ़/मूक पत्रिका

लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम छापरपानी में 35 वर्षीय महिला और उसकी 10 माह की मासूम पुत्री की निर्मम हत्या के बहुचर्चित अंधे कत्ल की गुत्थी को रायगढ़ पुलिस ने सुलझाते हुए 65 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अत्यंत संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण इस प्रकरण की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनके निर्देशन में थाना प्रभारी लैलूंगा द्वारा गांव में कैंप लगाकर लगातार साक्ष्य जुटाए गए और वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से की गई विवेचना के आधार पर आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली।घटना के संबंध में 16 जुलाई 2026 को ग्राम छापरपानी की महिला ने थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 35 वर्षीय मौसेरी बहन, जिसके पति की मृत्यु के बाद मानसिक स्थिति सामान्य नहीं रहती थी, गांव के प्रहलाद बेहरा के खेत स्थित बोर मकान में अपनी 10 माह की पुत्री के साथ रह रही थी। उसी दिन सुबह महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली, जबकि उसकी 10 माह की पुत्री की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी। महिला के सिर एवं चेहरे पर किसी भारी वस्तु से गंभीर चोट के निशान थे। उपचार के दौरान महिला की भी मृत्यु हो गई।सूचना मिलते ही एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी, थाना लैलूंगा पुलिस, एफएसएल एवं डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य संकलित किए। मामले में थाना लैलूंगा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 230/2026 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। घटनास्थल सुनसान होने, प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिलने तथा महिला का किसी से विवाद नहीं होने के कारण जांच बेहद चुनौतीपूर्ण थी। एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन पर थाना प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव ने ग्राम छापरपानी में लगातार कैंप लगाकर ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। इसी दौरान पुलिस को लगाये मुखबीरों से ग्राम कोड़ासिया निवासी भिखारीराम नागवंशी (65 वर्ष) के घटना के संबंध में जानकारी और अहम सबूत मिले । संदेह के आधार पर उसे पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया जिसके हाथ में चोट का निशान था, लेकिन उसने घटना से इंकार किया। पुलिस ने वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो आरोपी टूट गया और उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि 15 जुलाई की रात वह प्रहलाद बेहरा के खेत स्थित बोर मकान पहुंचा, जहां महिला अपनी बच्ची के साथ सो रही थी।

वेतन के आधार पर सरकारीकर्मियों को मिलेगा बिना ब्याज अल्पावधि ऋण, सरकारीकर्मियों को आकस्मिक जरूरतों के लिए अब ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने की आवश्यकता नहीं

ई-कोष से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

राज्य के शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध बिना ब्याज के अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के हाथों जुलाई माह में हो चुका है। यह सुविधा ई-कोष प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी। कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण एवं सहमति की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ऋण स्वीकृति एवं वितरण त्वरित रूप से किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार पूरी व्यवस्था में डेटा सुरक्षा, गोपनीयता तथा डिजिटल प्रमाणीकरण के उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया है।यह कर्मचारी कल्याण, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक, त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। अब कर्मचारी आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर कार्य करेंगे।आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों अथवा ऊंची ब्याज दरों पर बैंक से ऋण लेने की विवशता का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।राज्य सरकार ने उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित की है, जिसके माध्यम से वे बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया के अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। वित्त विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हुए इस सुविधा को ई-कोष प्रणाली से एकीकृत किया है। यह व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस, सुरक्षित और पारदर्शी है तथा इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आएगा।

रायगढ़ के जंगल में गूंजी नन्हे हाथी की किलकारी, मादा हाथी ने दिया शावक को जन्म

रायगढ़/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ वन परिक्षेत्र के बंगुरसिया सर्किल में पिछले कई दिनों से 18 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। इसी झुंड की एक मादा हाथी ने जंगल में शावक को जन्म दिया है। जन्म के बाद मौके पर मिले जैविक अवशेष (बर्थ वेस्ट) से इसकी पुष्टि हुई। इसके बाद से वन विभाग ड्रोन की मदद से पूरे दल की लगातार निगरानी कर रहा है।जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात कक्ष क्रमांक 915 स्थित तालाब के पास जंगल से हाथियों के तेज चिंघाड़ने की आवाजें सुनाई दीं। उस समय वनकर्मी गश्त पर थे। आवाज सुनकर वे मौके तक पहुंचने का प्रयास करने लगे, लेकिन जंगल में हाथियों के फैले होने के कारण सुरक्षा कारणों से पास नहीं जा सके।बुधवार सुबह करीब 5 बजे हाथियों का दल आगे बढ़ा, जिसके बाद वनकर्मी मौके पर पहुंचे। वहां उन्हें हाथी के शावक के जन्म के बाद निकलने वाली झिल्ली और खून के निशान मिले। इससे उन्होंने शावक के जन्म की पुष्टि की और इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद विभाग ने ड्रोन के जरिए हाथियों के दल की निगरानी शुरू कर दी।

कई दिनों से इसी क्षेत्र में था हाथियों का दल

बंगुरसिया सर्किल प्रभारी प्रेमा तिर्की ने बताया कि हाथियों का झुंड पिछले कई दिनों से इसी जंगल में मौजूद है। संभवतः शावक के जन्म के कारण ही दल ज्यादा दूर नहीं जा रहा था। कई बार हाथियों का झुंड सड़क पर भी आकर काफी देर तक खड़ा रहता था। ऐसे में विभाग लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है।

वन विभाग के लिए अच्छी खबर

रेंजर संजय लकड़ा ने बताया कि जंगल में हाथी के शावक का जन्म वन विभाग के लिए अच्छी खबर है। फिलहाल ड्रोन से पूरे दल की निगरानी की जा रही है। शावक के जन्म के बाद अब इस दल में हाथियों की संख्या 18 से बढ़कर 19 हो गई है, जबकि शावकों की संख्या तीन हो गई है। साथ ही प्रभावित गांवों के लोगों को जंगल में अकेले नहीं जाने और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

समय रहते किसान कराएं पंजीयन, गांव-गांव पहुंच रही राजस्व-कृषि विभाग की टीम

एग्रीस्टेक पंजीयन नहीं तो खाद-बीज और धान खरीदी में आ सकती है परेशानी

बलरामपुर/मूक पत्रिका

दुर्गेश गुप्ता । जिले में किसानों को डिजिटल कृषि सेवाओं और शासकीय योजनाओं से जोड़ने के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन अभियान तेज कर दिया गया है। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीमें गांव-गांव पहुंचकर किसानों का पंजीयन करा रही हैं। किसानों की सुविधा के लिए सेवा सहकारी समितियों, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), उचित मूल्य दुकानों, पंचायतों और विभिन्न पंजीयन शिविरों में भी व्यवस्था की गई है।

एग्रीस्टेक आईडी से मिलेंगे योजनाओं के लाभ

एग्रीस्टेक के माध्यम से प्रत्येक किसान की डिजिटल पहचान तैयार की जा रही है। किसान आईडी बनने के बाद धान खरीदी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरक अनुदान, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि मशीनीकरण योजना सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा। इससे किसानों को बार-बार अलग-अलग कार्यालयों में दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता भी कम होगी।

पंजीयन नहीं कराने पर बढ़ सकती हैं दिक्कतें–कृषि सेवाओं के डिजिटल होने के कारण समय पर एग्रीस्टेक पंजीयन नहीं कराने वाले किसानों को भविष्य में खाद-बीज प्राप्त करने, धान विक्रय, डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। प्रशासन ने किसानों से समय रहते पंजीयन कराने की अपील की है।

17 अगस्त से शुरू होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे–प्रशासन के अनुसार आगामी 17 अगस्त से डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू होने जा रहा है। जिन किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन्हें डिजिटल क्रॉप सर्वे में परेशानी हो सकती है, जिसका असर भविष्य में धान विक्रय पर भी पड़ सकता है। ऐसे में किसानों के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन कराना बेहद जरूरी बताया गया है।

संयुक्त खाताधारकों का अलग-अलग पंजीयन जरूरी–यदि किसी भूमि खाते या ऋण पुस्तिका में दो या अधिक व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं तो सभी खाताधारकों को अपना अलग-अलग एग्रीस्टेक पंजीयन कराना होगा। इसी तरह एक खाते में अलग-अलग किसानों के नाम से अलग-अलग खसरा नंबर दर्ज होने पर संबंधित किसानों को अपने-अपने खसरा नंबर का पंजीयन एवं मैपिंग कराना आवश्यक है।

पुराने किसानों को दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं–वर्ष 2025-26 में जिन किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन हो चुका है और एग्रीस्टेक आईडी जारी हो गई है, उन्हें दोबारा नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि भूमि, रकबा, खसरा, बैंक खाता, नॉमिनी या अन्य विवरण में परिवर्तन होने पर आवश्यक संशोधन और खसरा मैपिंग कराई जा सकती है। नई भूमि खरीदने वाले किसानों को केवल नई भूमि का खसरा मैपिंग कराना होगा।

नए किसानों के लिए पंजीयन अनिवार्य–नए किसानों को पहले एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। इसके बाद संबंधित समिति में भूमि का खसरा मैपिंग कराया जाएगा। पंजीयन के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी, भूमि संबंधी दस्तावेज और नॉमिनी की जानकारी आवश्यक होगी।

बकेट क्लेम भी जरूरी–जिन किसानों के पास एक से अधिक खसरा या खाते हैं और जिन्हें समूह के रूप में बकेट में चिन्हांकित किया गया है, उन्हें अपना बकेट क्लेम कराना अनिवार्य है। बकेट क्लेम सही तरीके से नहीं होने पर धान विक्रय के समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

राशन के साथ उचित मूल्य दुकान में करा सकते हैं पंजीयन–किसानों की सुविधा के लिए उचित मूल्य दुकानों में भी एग्रीस्टेक पंजीयन की व्यवस्था की गई है। किसान राशन लेने के साथ अपना पंजीयन भी करा सकते हैं। इसके अलावा सीएससी, सेवा सहकारी समिति, पटवारी कार्यालय, पंचायत एवं कृषि विभाग के शिविरों में भी सुविधा उपलब्ध है।

घर-घर पहुंच रही टीमें–राजस्व अधिकारियों द्वारा लगातार मैदानी क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर विशेष टीमें गठित कर डोर-टू-डोर संपर्क किया जा रहा है। अपंजीकृत किसानों को जानकारी देकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीयन केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। शिविरों से पहले मुनादी कर ग्रामीणों को भी सूचना दी जा रही है।

किसान स्वयं भी कर सकते हैं पंजीयन–किसान एग्रीस्टेक के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर स्वयं भी पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन की स्थिति एग्रीस्टेक आईडी के माध्यम से किसान स्वयं, सीएससी, समिति, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा पटवारी के माध्यम से जांच सकते हैं। प्रशासन की अपीलः सभी किसान आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर एवं भूमि संबंधी आवश्यक दस्तावेज लेकर अपने निकटतम पंजीयन केंद्र पहुंचकर जल्द से जल्द एग्रीस्टेक पंजीयन कराएं, ताकि भविष्य में खाद-बीज, धान खरीदी एवं विभिन्न शासकीय कृषि योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

संपादकीय

बहस के बिना कानून- लोकतंत्र में जरूरी है संवाद

अहम सवाल यह है कि संविधान में संसद सत्र आयोजित किए जाने की जो व्यवस्था की गई है, क्या उसका मूल उद्देश्य पूर्ण हो पा रहा है? अगर किसी कानून या योजना को सक्षम एवं कारगर बनाने में विपक्ष की कोई भूमिका न हो, तो संसद की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जहां जनकल्याण से जुड़े मसलों पर मंथन किया जाता है और उसके निष्कर्षों के आधार पर नीति निर्माण का खाका तैयार किया जाता है। जनता की आकांक्षाओं को आकार देने और देश को लोकतांत्रिक दिशा प्रदान करने में संसद की भूमिका सर्वोपरि है। आमजन की यह उम्मीद होती है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनकी समस्याओं, चिंताओं एवं जरूरतों को संसद में रखेंगे और उन पर विचार-विमर्श के बाद एक सक्षम कानून या योजना बनाई जाएगी। मगर, जब संसद में व्यापक चर्चा के बिना ही किसी विधेयक को पारित कर कानून की शक्ल दे दी जाए, तो उसकी समग्र व्यावहारिकता और सार्थकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।संसद के मानसून सत्र में अब तक ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। हाल ही में विद्यार्थियों के आंदोलन से निकले लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को व्यापक चर्चा और सुझावों के बिना ही पारित कर दिया गया और सोमवार को दो अन्य विधेयकों को भी इसी तरह से मंजूरी दे दी गई।अहम सवाल यह है कि संविधान में संसद सत्र आयोजित किए जाने की जो व्यवस्था की गई है, क्या उसका मूल उद्देश्य पूर्ण हो पा रहा है? अगर किसी कानून या योजना को सक्षम एवं कारगर बनाने में विपक्ष की कोई भूमिका न हो, तो संसद की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? इसमें दोराय नहीं कि सदन को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की है। मगर जब विपक्ष कोई सवाल या समस्या उठाता है, तो उसका निराकरण करना सत्तापक्ष का दायित्व होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्तापक्ष अपनी जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकता। संसद के मानसून सत्र की अब तक की अवधि पर नजर डालें, तो हंगामा और कार्यवाही का स्थगन, इन्हीं दो बातों पर जोर दिया गया है।ऐसा लगता है कि स्थगन, कार्यवाही का पर्याय बन गया है। विपक्ष नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दों को लगातार संसद में उठा रहा है और हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित हो जाती है। इस बीच महत्त्वपूर्ण विधेयक भी व्यापक चर्चा के बिना ही पारित हो जाते हैं।संसद में बने इस गतिरोध को दूर करने के बजाय आरोप-प्रत्यारोप के जरिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज कर लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है, तो सत्तापक्ष का दावा है कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है।

वातानुकूलन से गहराता पर्यावरण संकट

(रविशंकर कुमार)

दूसरी ओर, समाज का संपन्न वर्ग अपने घरों में बहुत ज्यादा जरूरत न होने पर भी एसी चला देता है। निजी तौर पर घरों में शीतलन का यह बेलगाम उपभोग पर्यावरण संकट को और गंभीर बना रहा है। शहरों में लाखों की संख्या में एसी सीधे तौर पर तंग और घनी गलियों में गर्म हवा फेंकते हैं। देश के सघन शहरी केंद्रों में यह स्थिति 'अर्बन हीट आइलैंड' के प्रभाव को इतना बढ़ा देती है कि फुटपाथ पर चलने वाले राहगीरों, रेहड़ी-पटरी वालों और बिना एसी वाले गरीब परिवारों के लिए सार्वजनिक रास्ते 'थर्मल डेथ ट्रैप' यानी खतरनाक ताप क्षेत्र में तब्दील हो जाते हैं।

फ्रांस से भारत जो सबसे बड़ा सबक सीख सकता है, वह है हर घर में अलग से एसी लगाने के विकेंद्रीकृत माडल को सिरे से खारिज करना।वैश्विक ताप लगातार बढ़ रहा है और अब इसका असर दुनिया भर में साफ देखा जा रहा है। पृथ्वी के ठंडे क्षेत्र माने जाने वाले यूरोप और उत्तरी अमेरिका भी इससे अछूते नहीं हैं। यानी जलवायु संकट एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश के लिए जहां अगले दो दशकों में शीतलन (कूलिंग) की मांग आठ गुना बढ़ने का अनुमान है, वहां गर्मी से निपटने का तात्कालिक उपाय घरों में एअर-कंडीशनर (एसी) लगा देने को ही माना जा रहा है।

मगर, इसके दूसरे पहलू पर गंभीरता से गौर करना जरूरी नहीं समझा जा रहा है। दरअसल, एसी कमरे को ठंडा करने के लिए उसकी गर्मी को बाहर फेंकता है और इससे निकलने वाली हानिकारक गैसों से पर्यावरण को और ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में हमें फ्रांस जैसी विकसित अर्थव्यवस्था के नीतिगत संयम पर गौर करना चाहिए, जहां भयंकर गर्मी के बावजूद बड़े पैमाने पर निजी एअरकंडीशनिंग को हतोत्साहित करने की नीति है।

देश के कई हिस्सों में मानसून आने से पहले उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर देती है। दोपहर के वक्त तकनीकी उपकरणों पर तापमान 39 या 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज होता है, जो देखने में ज्यादा कष्टकारी नहीं लगता। मगर हमारा शरीर इस आंकड़े को सिरे से खारिज करते हुए हकीकत का एक तकलीफदेह पन्ना खोलता है।

शरीर को महसूस होने वाला वास्तविक तापमान (फील्स-लाइक) असल में 49 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह कोई मानसिक भ्रम नहीं है, बल्कि 'हीट इंडेक्स' (ऊष्मा सूचकांक) का वह सच है, जो साबित करता है कि हमारे पारंपरिक मौसम विज्ञान के पैमाने मानव शरीर के वास्तविक संकट को मापने में नाकाम साबित हो रहे हैं।

जब मानसून में देरी होती है, तो अरब सागर से आने वाली नमी से भरपूर दक्षिण-पश्चिमी हवाएं जैसे ही मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं, तो सापेक्ष आर्द्रता का स्तर 60 से 70 फीसद तक पहुंच जाता है। मानव शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीने का सहारा लेता है, जो त्वचा से वाष्पीकृत होकर आंतरिक गर्मी को बाहर निकालता है।

मगर जब आसपास की हवा में पहले से नमी की मात्रा ज्यादा होती है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। पसीना त्वचा पर ही जमा रहता है, जिससे शरीर को ज्यादा गर्मी का एहसास होता है। यह स्थिति कई बार हमें 'वेट-बल्ब टेंपरेचर' की उस अंतिम सीमा के करीब ले आती है, जिसके पार गर्मी असहनीय हो जाती है। पहले इसे केवल वैश्विक दक्षिण देशों की समस्या माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में महसूस की गई गर्मी ने यह साबित कर दिया है कि यूरोप और अमेरिका के ठंडे इलाके भी उच्च-आर्द्रता वाले ताप संकट से अब अछूते नहीं हैं।

हालांकि, इस स्थिति के बावजूद फ्रांस ने अपने यहां घरेलू एसी के इस्तेमाल को महज पच्चीस फीसद तक सीमित रखा है, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा नब्बे फीसद से अधिक है। निजी तौर पर 'एअरकंडीशनिंग' को एक बुनियादी मानव अधिकार न मानने का फ्रांस का यह फैसला कोई जिद नहीं, बल्कि एक कड़वे पारिस्थितिक सच की स्वीकारोक्ति है।

फ्रांस केवल सांस्कृतिक रूप से एसी को हतोत्साहित नहीं करता, बल्कि इसके लिए वहां कड़े वैधानिक कानून हैं। फ्रांस के राष्ट्रीय 'एनर्जी कोड' (ऊर्जा संहिता) के तहत व्यावसायिक और सार्वजनिक भवनों में तब तक एसी चलाने की कानूनी मनाही है, जब तक कि अंदर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस को पार न कर जाए। इसके अलावा, यदि कोई दुकानदार एसी चालू रखकर दुकान का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ता है, तो स्थानीय निकाय उस पर भारी जुर्माना लगा सकता है।

इसके विपरीत भारत का मौजूदा प्रशासनिक माडल आज भी परंपरागत सिद्धांत पर चल रहा है। जब मैदानी इलाकों में 'हीट इंडेक्स' 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तब भी मौसम विभाग अपने पुराने पैमानों के आधार पर आधिकारिक तौर पर 'लू' घोषित नहीं कर पाता, क्योंकि थर्मामीटर का सूखा तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही अटका होता है। नतीजा यह होता है कि बाहर काम करने वाले लोग मौसम उपकरणों के इस छलावे के बीच असल में 50 डिग्री महसूस किए जाने वाले तापमान के बीच रहने को मजबूर होते हैं।

दूसरी ओर, समाज का संपन्न वर्ग अपने घरों में बहुत ज्यादा जरूरत न होने पर भी एसी चला देता है। निजी तौर पर घरों में शीतलन का यह बेलगाम उपभोग पर्यावरण संकट को और गंभीर बना रहा है। शहरों में लाखों की संख्या में एसी सीधे तौर पर तंग और घनी गलियों में गर्म हवा फेंकते हैं।

देश के सघन शहरी केंद्रों में यह स्थिति 'अर्बन हीट आइलैंड' के प्रभाव को इतना बढ़ा देती है कि फुटपाथ पर चलने वाले राहगीरों, रेहड़ी-पटरी वालों और बिना एसी वाले गरीब परिवारों के लिए सार्वजनिक रास्ते 'थर्मल डेथ ट्रैप' यानी खतरनाक ताप क्षेत्र में तब्दील हो जाते हैं।

फ्रांस से भारत जो सबसे बड़ा सबक सीख सकता है, वह है हर घर में अलग से एसी लगाने के विकेंद्रीकृत माडल को सिरे से खारिज करना। पेरिस की ऐतिहासिक वास्तुकला को बचाने और उसकी सड़कों को 'अर्बन हीट आइलैंड' के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए वहां की सरकार ने एक वैकल्पिक तकनीक पर निवेश किया, जिसे 'क्लाइमस्पेस' कहा जाता है।

पेरिस की जमीन के नीचे पाइपलाइन के जरिए एक विशाल शीतलन तंत्र बिछाया गया है, जो सीन नदी से पानी लेकर उसे भूमिगत संयंत्रों में ठंडा करता है। फिर इस ठंडे पानी को पाइप के जरिए बड़े होटलों और सरकारी दफ्तरों तक पहुंचाया जाता है, जो उन्हें ठंडा रखता है। यह पारंपरिक एसी के मुकाबले पैंतीस फीसद कम बिजली की खपत करता है और कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर रखता है। अगर भारत में स्मार्ट शहरों और शहरी पुनर्विकास योजनाओं के मास्टर प्लान में इस तकनीक को शामिल किया जाए, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बढ़ते ताप की समस्या से निपटा जा सकता है। हमें शीतलन को एक निजी उपभोक्ता उत्पाद मानने के बजाय इसे बिजली, पानी की तरह एक साझा 'सार्वजनिक बुनियादी ढांचा' मानना होगा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को केवल थर्मामीटर के सूखे तापमान के बजाय 'संयुक्त ऊष्मा जोखिम सूचकांक' को प्रशासनिक कार्रवाई का वैधानिक आधार बनाना चाहिए। इसके साथ ही फ्रांसीसी माडल की तर्ज पर वाणिज्यिक परिसरों, सरकारी दफ्तरों और हवाईअड्डों के लिए एसी के तापमान की न्यूनतम सीमा अनिवार्य रूप से 24 डिग्री सेल्सियस तय की जानी चाहिए, ताकि बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। फ्रांस अपनी चूना पत्थर की दीवारों पर भरोसा करता है, जो गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं। भारत को अपने 'ऊर्जा संरक्षण भवन कोड' को स्थानीय स्तर पर कड़ाई से लागू करना होगा। इमारतों की दिशा को धूप के हिसाब से तय करना, छतों पर हल्के रंग के कूल-रूफ पेंट लगाना और खोखली ईंटों का उपयोग करना जैसी तकनीकों से घरों के अंदरूनी तापमान को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। वक्त आ गया है कि भारत पारंपरिक थर्मामीटर की सीमित सोच से आगे बढ़े, निजी एसी के बेलगाम उपभोग पर लगाम लगाए और एक ऐसा सामूहिक ढांचा तैयार करे, जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम कर सके।

नया भारत और जेन जेड की भूमिका

(शिवेंद्र कुमार पाण्डेय)

देश एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एक्सप्रेसवे का बिछता जाल, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रांति, और स्टार्टअप कल्चर ने विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए भारत को दुनिया में अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य से लेकर देश के कोने-कोने तक विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। ऐसे समय में, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी 'जेन-जी' (जेन जेड) यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी वह युवा पीढ़ी है, जो डिजिटल तकनीक के माहौल में ही पली-बढ़ी है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि मौजूदा दौर में जेन-जी की देश व समाज के प्रति क्या भूमिका होनी चाहिए? यह सवाल इसलिए कि नीट पेपर लीक के खिलाफ हालिया प्रदर्शन में यही जेन-जी कुछ राजनीतिक दलों का टूल बनते दिखाई दिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी घटना के विरोध का, अपनी बात कहने का, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सबको अधिकार है। लेकिन, देश के प्रधानमंत्री को भद्दी गालियां देना और अश्लील संकेतों का प्रदर्शन संस्कारविहीन होने का परिचय मात्र है। ऐसा करने वाले युवाओं ने क्या एक बार भी सोचा कि जब उनके माता-पिता या परिवार के बुजुर्ग उन्हें टीवी पर यह सब कहते-करते देखेंगे तो उन्हें समाज में कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जेन-जी यह क्यों भूल रहे हैं कि विकसित भारत का सपना उन्हें ही आगे लेकर जाना है। वैश्विक मंच पर भारत को स्थापित करने में उनकी भूमिका नेतृत्वकर्ता की होनी चाहिए। इस अभूतपूर्व विकास काल में देश व समाज को युवाओं की ठोस सकारात्मक भूमिका का इंतजार है। आज अधिसंख्य युवा केवल परंपरागत नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय जोखिम उठाने और इनोवेशन में विश्वास रखते हैं। उत्तर प्रदेश और देश के टियर-2 तथा टियर-3 शहरों से जिस प्रकार एग्रीटेक, एडटेक और फिनटेक स्टार्टअप्स उभर रहे हैं, उसमें जेन-जी की केंद्रीय भूमिका है। उत्तर प्रदेश की 'एक जिला-एक उत्पाद' जैसी योजनाओं को डिजिटल पहचान दिलाने और स्थानीय कारीगरों को वैश्विक बाजार से जोड़ने में युवाओं की तकनीकी दक्षता वरदान साबित हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और तकनीक को केवल मनोरंजन का साधन न बनाकर उसका उपयोग फार्मिंग, हेल्थ सर्विसेज और शिक्षा को सुगम बनाने में करना बेहतर होगा। आर्थिक प्रगति तब तक अधूरी है जब तक वह पर्यावरण के अनुकूल न हो। जेन-जी को जलवायु के प्रति जागरूक पीढ़ी माना जाता है। विकास की दौड़ में यदि प्रकृति पीछे छूट गई, तो वह प्रगति स्थायी नहीं हो सकती। जेन-जी का दायित्व है कि वह टिकाऊ और प्रकृति-अनुकूल जीवनशैली को अपनाए। सिंगल-यूज प्लास्टिक का बहिष्कार, ई-कचरे का सही निपटान, और अक्षय ऊर्जा (सौर/पवन ऊर्जा) के प्रति जागरूकता फैलाना, ऐसा व्यवसाय और जीवनशैली चुनना जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करे, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां युवाओं की प्रभावी भागीदारी तस्वीर बदल सकती है। जेन-जी 'डिजिटल नेटिव' है, यानी यह पहली ऐसी पीढ़ी है जिसके पास सूचनाओं का अथाह भंडार अंगुलियों पर उपलब्ध है। लेकिन इस डिजिटल ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। फैक्ट चेक के माध्यम से फेक न्यूज व हेट स्पीच के प्रचार-प्रसार पर काफ हद तक रोक लगाई जा सकती है। सोशल मीडिया पर बिना जांच-परख के किसी भी संवेदनशील खबर को शेयर करने से बचना और डिजिटल स्पेस को सुरक्षित व सकारात्मक बनाना समय की मांग है। समाज में समरसता व सौहार्द का संदेश देने वाले सकारात्मक कंटेंट बनाइए, इंटरनेट पर ट्रोलिंग या नफरत फैलाने के बजाय दूसरों के मानसिक स्वास्थ्य और विविधता का सम्मान करें। राष्ट्र केवल सरकारों से नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिकों से बनता है। जेन-जी को अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी उतना ही सचेत रहना होगा। सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना, स्वच्छता अभियानों का नेतृत्व करना और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को नकारना तथा एक समावेशी समाज का निर्माण करना। केवल ऑनलाइन बहस करने के बजाय शत-प्रतिशत मतदान में हिस्सा लेना और शासन व्यवस्था में नीतिगत सुधारों के लिए हिंसक प्रदर्शन के बजाय तार्किक आवाज उठाना। जेन-जी से ऐसी ही जिम्मेदारियों की अपेक्षा की जाती है। युवावस्था में बागी तेवर अपनाना कोई नई बात नहीं, ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि यह अदम्य ऊर्जा गलत दिशा में न जाए, चंद राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थ के लिए इसका फायदा न उठा सकें। विकास की दौड़ में अक्सर अंदेशा रहता है कि युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कट न जाएं। भारत की असली ताकत उसकी प्राचीन विरासत और आधुनिक दृष्टि के अनूठे संगम में है।

एनडीए सांसदों के सत्रीय 'मंगल मिलन' के सियासी मायने

(कमलेश पांडे)

इसमें एनडीए के सभी प्रमुख घटक दलों के सांसद शामिल हुए, जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी ,जनता दल (यूनाइटेड) ,तेलगु देशम पार्टी ,लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ,हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ,अपना दल (सोनेलाल) अन्य एनडीए सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए। खास बात यह कि पहली बार नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया ,के सांसद भी बैठक में शामिल हुए, क्योंकि पार्टी को हाल में एनडीए का सहयोगी बनाया गया है।

भाजपा नेतृत्व ने अपने सर्वाधिक संकटग्रस्त काल से गुजरते हुए अपने सांसदों और सहयोगी सांसदों को याद किया, जिसे राजनीतिक गलियारे में एनडीए सांसदों के 'मंगल मिलन' की उपमा दी गई है। हालांकि यह अनौपचारिक बैठक, संवाद या सामूहिक कार्यक्रम संसद सत्र के दौरान हरेक मंगलवार को आहूत होती है।

केंद्र में पिछले 12 वर्षों से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार इन दिनों पुनः उस एकजुट विपक्ष के निशाने पर है, जिसे वह अबतक चुनावी सियासी पाट पर पछाड़ते आई है। लेकिन जिस तरह से बहुरूपिया विपक्ष कभी मुसलमानों के छद्म वेश में, कभी किसानों के रूप में और कभी छात्रों के छद्म वेश में जिस तरह से मोदी सरकार को घेरने पर तुला हुआ है, उसके पीछे विदेशी हाथ से इंकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी सरकार सबसे जूझ रही है!

हाल ही में छात्र आंदोलन की कथित सफलता से घबराई सरकार ने जिस तरह से अपने ओबीसी रणनीतिकार शिक्षा मंत्री की राजनीतिक बलि चढ़ाई है, और इससे उत्साहित कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने जिस घमंड का प्रदर्शन किया, उससे विपक्ष उत्साहित है। यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर लिया जाने लगा है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का अतीत और खुद देश का भविष्य करार दिया है, उसके मुताल्लिक इतना ही इशारा करना काफी होगा कि भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने देश का भविष्य तय कर दिया है और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आगे करके एक तीर से कई शिकार करने की योजना बनाई है, क्योंकि भाजपा की ओबीसी राजनीति में श्री चौधरी अपने नैसर्गिक सियासी गुणों के चलते फिट बैठते हैं। ये अभी अंदरखाने की बात है, लेकिन राहुल गांधी को आगाह करने के लिए मैंने इस सच्चाई को डिस्क्लोज कर दिया है, जो हिंदी पट्टी के मिजाज पर फिट बैठता है।

शायद यही वजह है कि भाजपा नेतृत्व ने अपने सर्वाधिक संकटग्रस्त काल से गुजरते हुए अपने सांसदों और सहयोगी सांसदों को याद किया, जिसे राजनीतिक गलियारे में एनडीए सांसदों के मंगल मिलन की उपमा दी गई है। हालांकि यह अनौपचारिक बैठक, संवाद या सामूहिक कार्यक्रम संसद सत्र के दौरान हरेक मंगलवार को आहूत होती है। हालिया एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक गत 28 जुलाई 2026 (मंगलवार) को, संसद के मानसून सत्र के दौरान हुई।

यह मंगल मिलन नाम से आयोजित होने वाली नियमित मंगलवार की संसदीय दल की बैठक थी। जो नई दिल्ली में संसद पुस्तकालय भवन के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, संसदीय कार्य मंत्री तथा एनडीए के अनेक सांसद और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

इसमें एनडीए के सभी प्रमुख घटक दलों के सांसद शामिल हुए, जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी ,जनता दल (यूनाइटेड) ,तेलगु देशम पार्टी ,लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ,हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ,अपना दल (सोनेलाल) अन्य एनडीए सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए। खास बात यह कि पहली बार नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया ,के सांसद भी बैठक में शामिल हुए, क्योंकि पार्टी को हाल में एनडीए का सहयोगी बनाया गया है। इस बैठक की सबसे चर्चित बात एनसीपीआई सांसदों की पहली भागीदारी रही, जिसे एनडीए के विस्तार और संसद में संख्या एवं राजनीतिक समन्वय को मजबूत करने के संकेत के रूप में देखा गया।

इस मंगल मिलन के कई राजनीतिक और संगठनात्मक संकेत/मायने निकलकर सामने आते हैं-

पहला, संगठनात्मक एकजुटता का प्रदर्शन- यह विपक्ष और सहयोगी दलों को संदेश कि एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं और सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं।

दूसरा, संसद सत्र की रणनीति- संसद में सरकार के विधेयकों, विपक्ष की रणनीति और विभिन्न मुद्दों पर साझा रुख तय करने का अवसर समझा जाता है।

तीसरा, आगामी चुनावों की तैयारी- देश के अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले सांसदों को बूथ स्तर तक सक्रिय रहने और जनता से संवाद बढ़ाने का संदेश दिया गया।

चौथा, सरकार की उपलब्धियों का प्रचार- सांसदों को निर्देश दिया जा सकता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुँचाएं।

पांचवां, सहयोगी दलों को महत्व- एनडीए में शामिल छोटे और क्षेत्रीय दलों को सम्मान और भागीदारी का संदेश देकर गठबंधन को मजबूत बनाए रखना है। छठा, विपक्षी इंडिया गठबंधन को राजनीतिक संदेश- यह दिखाना कि एनडीए में नेतृत्व को लेकर कोई असमंजस नहीं है और गठबंधन स्थिर है। सातवां, 2029 की दीर्घकालिक रणनीति- केवल वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों पर नहीं, बल्कि अगले लोकसभा चुनाव तक संगठन और जनसंपर्क को मजबूत करने की दिशा में तैयारी। उल्लेखनीय है किभारतीय राजनीति में ऐसे कार्यक्रम अक्सर केवल सामाजिक मेल-मिलाप नहीं होते, बल्कि इनके माध्यम से राजनीतिक संदेश दिए जाते हैं, सांसदों का मनोबल बढ़ाया जाता है, संगठनात्मक अनुशासन मजबूत किया जाता है, और भविष्य की रणनीति पर अनौपचारिक चर्चा होती है। इसलिए मंगल मिलन को केवल सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के बजाय राजनीतिक समन्वय, गठबंधन प्रबंधन और चुनावी तैयारी के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी देखा जा सकता है। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक है) (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

कृषि महाविद्यालय बेमेतरा में पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

बेमेतरा/मूक पत्रिका

रेवेन्द्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, ढोलिया-बेमेतरा में अधिष्ठाता डॉ. अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना (ह्रस्र्) इकाई द्वारा ÷पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन÷ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ÷सुरक्षित पर्यावरण एवं सुरक्षित भविष्य÷ विषय पर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य, आत्मानुशासन एवं सकारात्मक जीवनशैली के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात प्रजापिता ब्रह्माकुमारी, बेमेतरा से उपस्थित शशि दीदी एवं पियूष भाई ने छात्र-छात्राओं से परिचर्चा करते हुए पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने प्रदूषण को कम करने, अधिक से अधिक पौधरोपण करने, प्राकृतिक एवं उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने तथा जीव-जंतुओं की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया।कार्यशाला के दौरान पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विद्यार्थियों को मन की एकाग्रता, स्वयं की पहचान, क्रोध पर नियंत्रण, प्रसन्नचित्त रहने, समय प्रबंधन तथा आत्मिक शक्ति को मजबूत बनाए रखने के उपाय भी बताए गए। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल बाहरी प्रकृति तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के मानसिक एवं आंतरिक वातावरण को सकारात्मक रखना भी उतना ही आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं छात्र-छात्राओं को लगभग 5 मिनट का ध्यान अभ्यास कराया गया। साथ ही विद्यार्थियों को मोबाइल फोन के अनावश्यक उपयोग को कम करने तथा अध्ययन, स्वास्थ्य एवं रचनात्मक गतिविधियों के लिए समय का सदुपयोग करने की सलाह दी गई।इस अवसर पर डॉ. इजी यू. के. ध्रुव प्रभारी अधिष्ठाता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण डॉ. टी. डी. साहू, डॉ. असित कुमार, कुंती बंजारे, डॉ. भारती बघेल, डॉ. हेमलता निराला, राजेश्वरी कुर्रे, डॉ. साक्षी बजाज, प्रतिभा सिंह, डॉ. सरिता शर्मा, डॉ. महानंद, डॉ. रामेश्वर एवं संजीव गुर्जर सहित महाविद्यालय के समस्त कर्मचारीगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के साथ उन्हें आपदा एवं विपरीत परिस्थितियों के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ, सकारात्मक एवं अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।

तराईमाल में स्वच्छता को बढ़ावा देने पहल, नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड ने ग्रामीणों को बांटे डस्टबिन..

रायगढ़/मूक पत्रिका

ग्राम पंचायत तराईमाल में नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड की ओर से स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डस्टबिन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम उद्योग समूह से जुड़े ओमप्रकाश जिंदल के जन्मदिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित किया गया।

कार्यक्रम ग्राम पंचायत के समरसता भवन में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ पंच और सरपंच मौजूद रहे। इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से ग्रामीणों को डस्टबिन वितरित किए गए और घर व आसपास के क्षेत्र को साफरखने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में प्रबंधन की ओर से कहा गया कि स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। घरों से निकलने वाले कचरे को इधर-उधर फेंकने के बजाय डस्टबिन में रखने और उचित तरीके से उसका निपटारा करने की अपील की गई। ग्रामीणों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गांव में स्वच्छता को लेकर इस तरह के प्रयास लगातार होते रहने चाहिए। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों के बीच स्वच्छता और साफ-सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया।

नांदघाट-मुंगेली रोड होगा फोरलेन, राज्य शासन ने मंजूर किए 21.81 करोड़

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राशि स्वीकृति का पत्र जारी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

क्रमांक- FINACC-6084/2026/ENIC/PWD/T-3 नवा रायपुर, दिनांक 06-08-2026

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

विषय:- केन्द्रीय सड़क निधि योजनांतर्गत वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक बजट में ... बेमेतरा एवं मुंगेली के नांदघाट मुंगेली (राज्य मार्ग क्र.-10) किमी. 1 से 37/4 = लं. 36 ... स्वीकृत 02 लेन मार्ग को 4 लेन में परिवर्तित करने विषयक। (आकस्मिकता निधि अग्रिम स्व...

संदर्भ:-(1) आपका पत्र क्रमांक-25290/बजट/034/2026, दिनांक 11.06.2026.
(2) विभागीय पत्र क्र.-एफ 18-08/2025/19/तक.-3, दिनांक 16.05.2025. (राशि रू. ... लाख, मांग संख्या 24/5054-(03)-(337)-0101-(8716) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के... निधि रु 97)
(3) विभागीय पत्र क्र.-FINACC/4710/2025-EINC/PWD/T-3 दिनांक 30.10.2025, 534.68 लाख, मांग संख्या 24/5054-(03)-(337)-0101-(7991) सी.आर.एफ. अंतर्गत ... में राज्य शासन द्वारा व्यय # 97)

---000---

संदर्भित पत्र क्र.-1 के तहत आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर राज्य शासन एतद् ... बेमेतरा एवं मुंगेली के नांदघाट मुंगेली (राज्य मार्ग क्र.-10) किमी. 1 से 37/4 = लं. 36 ... स्वीकृत 02 लेन मार्ग को 4 लेन में परिवर्तित करने हेतु निर्माण कार्य के लिये राशि रू. ... आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुये लागत राशि रू. 21.81 करोड़ (रुपये इक्की... इक्यासी लाख मात्र) की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

1. आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति संबंधी छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र.-... FINACC/36-1783/ब-4/2026, दिनांक 03.08.2026 की प्रति संलग्न है, **निर्देशानुसार अग्रिम ... सुनिश्चित करें।**
2. कार्य का व्यय मांग संख्या 24/5054-(03)-(337)-0101-(7991)-#97-002 सी.आर.एफ. ... निर्माण कार्यों में राज्य शासन द्वारा व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।
3. कार्य की तकनीकी स्वीकृति (T.S.) सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य ... एवं शासकीय नियमों/निर्देशों में निर्दिष्ट समस्त औपचारिकताओं का पूर्णतः पालन सुनिश्चि... उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाये।
4. **प्राक्कलन में भू-अर्जन प्रस्तावित नहीं है, अतः स्वीकृति में भू-अर्जन हेतु राशि स्वीकृत न... प्रस्ताव अनुसार शासकीय भूमि पर ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जावें।**
5. शीर्ष में उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित किया जाये। सीमा से अधिक ... किया जाये।
6. निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करें।
7. कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। किसी भी स्त... की गुणवत्ता पर कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार ...

राज्य शासन ने बेमेतरा जिले के नांदघाट से मुंगेली जिला मुख्यालय तक टू-लेन सड़क के फोरलेन में उन्नयन के लिए 21 करोड़ 81 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से 36.40 किमी फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से राशि स्वीकृति के संबंध में प्रमुख अभियंता को परिपत्र जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री साव ने कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता को कार्य की निविदा समय-सीमा में करने, निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने निर्माण एजेंसी से अनुबंधित समय-सीमा में काम पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कराने को कहा है।कार्य पूर्ण किये जाने के लिए अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि नहीं किए जाने के भी निर्देश विभाग ने दिए हैं। अपरिहार्य एवं नियंत्रण से बाहर मान्य कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय-सीमा में वृद्धि की जा सकेगी। निर्माण कार्य की समयावधि में वृद्धि (Time E&tension) नियमानुसार अर्थदंड सहित अधिरोपित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पेड्रावन-सरसभांठा-बालपुर सड़क, स्वामी आत्मानंद स्कूल भवन और किसानों के लंबित मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

15 अगस्त तक मांगों का समाधान नहीं तो 17 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कार्यालय ग्राम पंचायत सरधाभांठा
जनपद पंचायत बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

विशाल कुमार
सरपंच
ग्राम पंचायत सरधाभांठा

मो.7049414527

प्रति,

माननीय कलेक्टर महोदया जी
जिला - सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्षेत्र की वर्षों पुरानी मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ग्राम पंचायत सरसभांठा एवं बालपुर के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि 15 अगस्त 2026 तक उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो 17 अगस्त 2026 से ग्रामीण लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे। ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग पेड्रावनङ्कसरसभांठाङ्कबालपुरङ्ककोसिर मार्ग के लगभग 7 किलोमीटर लंबे जर्जर सड़क मार्ग का निर्माण है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बरसात के दिनों में कीचड़ और जलभराव के कारण स्कूली बच्चों, किसानों, मरीजों और आम लोगों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने तथा तब तक सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। दूसरी प्रमुख मांग बालपुर स्थित स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन निर्माण से जुड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय भवन के लिए शासन से 1 करोड़ 21 लाख 16 हजार रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके कारण 500 से अधिक छात्र-छात्राओं को असुविधाजनक परिस्थितियों में पढ़ाई करनी पड़ रही है।ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य के दौरान बनाए गए पुल के बाद निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया था।

वहीं, बायपास सड़क निर्माण से प्रभावित किसानों का मुआवजा भी एसडीएम कार्यालय में लंबित है। ग्रामीणों ने प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा राशि वितरित कर सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है।ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि 15 अगस्त तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो 17 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन के साथ पंचायत प्रस्ताव, जर्जर सड़क की तस्वीरें तथा विद्यालय भवन की स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं।

स्कूल का अहाता बनना था, बन रही थी सीसी रोड: विरोध के बाद पंचायत ने रोका काम, सीमांकन के बाद होगा फैसला..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

ग्राम पंचायत साल्हेओना में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाहर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए अहाता निर्माण की जरूरत बताई जा रही है, लेकिन मौके पर सीसी रोड का निर्माण कराए जाने से स्कूल प्रबंधन और ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। मामले को लेकर सवाल उठने के बाद पंचायत ने फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया है।

अहाते की जरूरत के बीच सीसी रोड का निर्माण-जानकारी के अनुसार स्कूल परिसर के बाहर अहाता नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर पहले से समस्या बनी हुई है। स्कूल परिसर में आवारा पशुओं और बाहरी लोगों के प्रवेश की आशंका बनी रहती है। ऐसे में स्कूल के लिए अहाता निर्माण को जरूरी माना जा रहा है। इसी बीच स्कूल के बाहर सीसी रोड का निर्माण शुरू होने से मामला चर्चा में आ गया। ग्रामीणों और स्कूल प्रबंधन का कहना है कि जिस स्थान पर अहाता निर्माण होना चाहिए, वहां सड़क बनाए जाने से स्कूल की मूल समस्या दूर नहीं होगी।

स्कूल प्रबंधन की आपत्ति के बाद रुका काम-निर्माण को लेकर स्कूल प्रबंधन द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद पंचायत स्तर पर फिलहाल काम रोक दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य स्वीकृत कार्य से अलग तरीके से कराया जा रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए और सरकारी राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए।

सरपंच प्रतिनिधि ने बताई निर्माण की वजह-इस संबंध में ग्राम पंचायत साल्हेओना के सरपंच प्रतिनिधि शौकीलाल सहिस ने बताया कि जिस स्थान पर सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा था, उसके लिए गांव के दो-तीन किसानों ने आवेदन दिया था। किसानों ने बताया था कि सड़क के आगे उनके खेत हैं और इसके अलावा बाजार आने-जाने के लिए भी आम लोगों को सड़क की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत द्वारा जनसहयोग से सड़क निर्माण कराया जा रहा था। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा आपत्ति किए जाने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया है। स्कूल प्रबंधन को यह भी आश्वासन दिया गया है कि अहाता निर्माण के लिए सुरक्षित रखी गई भूमि से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब संबंधित भूमि का सीमांकन कराया जाएगा और सीमांकन के बाद जो स्थिति सामने आएगी, उसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

सीमांकन के बाद साफ होगी स्थिति-फिलहाल मामले में पंचायत और स्कूल प्रबंधन के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा कि सीमांकन के बाद सीसी रोड और प्रस्तावित अहाता निर्माण की स्थिति क्या रहती है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल की जरूरत और विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य स्पष्ट नियमों और पारदर्शिता के साथ कराया जाए।

एसबीआई बैंक में सैलरी एकाउंट को स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज एकाउंट में बदलने पर सरकारी कर्मियों को मिलेगा लाखों करोड़ का निशुल्क बीमा

छत्तीसगढ़ शासन और भारतीय स्टेट बैंक के अनुबंध से सरकारी कर्मियों को आपदा में मिलेगा राहत

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

FEATURES OF STATE GOVERNMENT SALARY PACKAGE (SGSP) FOR SERVING PERMANENT EMPLOYEES OF OFFICE OF STATE GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

Features	Silver	Gold	Diamond	Platinum	Rhodium
Eligibility (net salary)	10K to 25K	>25K to 50k	>50K to 100K	>100K to 200K	>200 K
Min. Balance	NIL (No minimum balance required to be maintained)				
Passbook	Free				
Internet Banking	Free				
Auto Sweep Facility (On request)	• Threshold Amount: Rs 35,000/- • TDRs/ STDRs to be created for a minimum amount of Rs.10,000/- (and in multiples of Rs.1,000/-) in any one instance.				
ATM cum Debit Card	Free, Domestic Classic Debit Card	Free, International Gold Debit Card		Free, International Platinum Debit Card	
New Age RuPay Card*	Complimentary International RuPay Platinum Debit Card			Complimentary International RuPay select Debit Card	
Transactions At ATM	State Bank & Other Bank ATMs: Unlimited Free				
Multi City Cheques	Cheque Leaf charges: NIL (except for bulk requirement i.e., in excess of 25 cheque leaves at a single instance in a month)				
Concession in annual locker rent	Nil		50%		
Setting up of Standing Instructions within SBI	Free				
RTGS/NEFT Charges	Waived (in online mode)				
SMS Alerts	Free				
Drafts Issue Charges	Unlimited Free, if issued through Salary Account				
Debit Cards	1. Existing option to continue 2. Additionally, feature packed new RuPay Cards to be mapped which are made available by NPCI (Details of features associated with RuPay Card is placed as Annexure-IV				
Personal Accidental Insurance (PAI) Death Cover*	Rs. 100 lakhs (All Variants)				
Air Accidental Insurance (AAI)	Rs. 160 lakhs (All Variants)				
Permanent Total Disability (PTD) Cover	Rs. 100 lakhs (all variants)				
Permanent Partial Disability (PPD) Cover	Rs. 80 lakhs (all variants)				
Add-On Insurance Covers (PAI)	Available as per the insurance policy provisions				
Group Term Life Insurance Cover	Rs. 10 Lakh (All Variants)				
Super Top-up Health Insurance	Rs. 15 lac/ Rs. 30 lac with Rs. 2 lac/Rs. 3 lac deductible, as per extant T&C of the MoU with Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd (Cost to be borne by the Customer, to be purchased voluntarily) (Details placed at Annexure-VI)				

10

SBI

Other Facilities	As applicable/ available to Regular Savings Bank account
Family Savings Account – SBI Rishtey	Available for Gold and above variants Salary Package Customers.
Concession in Processing Charges and Relaxation in margin on loan to SGSP account holders (Serving permanent employees)	
Home Loan	Processing fees - 100% (Charges for Title Investigation Report (TIR), Valuation etc. to be recovered from customers)
Car Loan	Processing fees - 50% or Minimum Rs 500 (Whichever is Higher)

छत्तीसगढ़ राज्य के नियमित शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों हेतु छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के साथ स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज पर विगत दिसंबर में अनुबंध हुआ है, जो 4 जनवरी 2026 से लागू है। अधिकारियों कर्मचारियों को अपने एसबीआई बैंक में वेतन खाते (सैलरी एकाउंट) को स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज एकाउंट में परिवर्तित (बदलना) करना होगा। इस अनुबंध से सरकारी कर्मियों और उनके परिजनों को दुर्घटना व अन्य आपदा में राहत मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के नियमित शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को इस अनुबंध से 1 करोड़ 60 लाख ? का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, राशि 100 लाख ? का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एवं राशि 10 लाख ? का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस आदि निशुल्क सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके अलावा रुपे कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त बीमा राशि भी निःशुल्क उपलब्ध रहेगा एवं हेल्थ इंश्योरेंस में टॉप अप रियायती दर पर उपलब्ध होगा। वित्त विभाग द्वारा संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुरुप राज्य के सभी एसबीआई खाताधारक नियमित अधिकारियों कर्मचारियों का विवरण एसबीआई बैंक को उपलब्ध करा दिया गया है।

100 बिस्तर अस्पताल निर्माण की गुणवत्ता पर फिर उठे सवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- नियमों को दरकिनार कर हो रहा घटिया काम..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

सरिया में बन रहे 100 बिस्तर अस्पताल के निर्माण को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरिया के अध्यक्ष उग्रसेन साहू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल निर्माण में निर्धारित मापदंडों और तकनीकी नियमों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराने की मांग की है।

शुरुआत से ही निर्माण कार्य पर उठ रहे सवाल-उग्रसेन साहू का आरोप है कि अस्पताल निर्माण की शुरुआत से ही कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिली हैं। उन्होंने कहा कि नींव और कॉलम की भराई में मुरुम की जगह छुई मिट्टी का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई थी। इसके अलावा सरिया, गिट्टी और सीमेंट सहित निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की टीम दो-तीन बार निर्माण स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले चुकी है और मौके पर मिली कथित खामियों से संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराया गया था।

कलेक्टर की जांच के बाद भी नहीं थमा विवाद-उग्रसेन साहू के मुताबिक शिकायतों के बाद स्वयं कलेक्टर द्वारा भी निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान कुछ कमियां सामने आने पर ठेकेदार को फटकार लगाए जाने की बात भी उन्होंने कही। इसके बावजूद निर्माण कार्य में कथित तौर पर नियमों की अनदेखी जारी रहने का आरोप लगाया गया है।

कॉलम की चौड़ाई और गहराई को लेकर गंभीर सवाल-कांग्रेस अध्यक्ष ने निर्माण के तकनीकी मापदंडों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि दस्तावेज के अनुसार कॉलम की चौड़ाई 300 एमएम और गहराई 400 एमएम निर्धारित है, लेकिन मौके पर कुछ कॉलम करीब 200 एमएम चौड़े और 300 एमएम गहरे बनाए जाने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि यदि निर्माणाधीन अस्पताल के सभी कॉलम और अन्य संरचनाओं की तकनीकी माप कराई जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। उनका आरोप है कि अभी तक जो कमियां सामने आई हैं, वे केवल एक हिस्से की हैं और पूरे निर्माण की जांच होने पर और भी खामियां सामने आने की संभावना है।

निर्माण एजेंसी से पक्ष जानने की कोशिश-मामले में निर्माण एजेंसी के अधिकृत कर्मचारी प्रकाश महंत से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया। उनसे निर्माण की गुणवत्ता और लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन वे संबंधित ठेकेदार और निर्माण कार्य को लेकर स्पष्ट जवाब देने के बजाय गोलमोल जवाब देते नजर आए। ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवाल और भी गंभीर हो गए हैं। हालांकि, निर्माण में गड़बड़ी के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में तकनीकी जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि निर्माण कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हुआ है या नहीं।

ओपी चौधरी के विधानसभा क्षेत्र में निर्माण, उठे राजनीतिक सवाल-100 बिस्तर का यह अस्पताल वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विधानसभा क्षेत्र सरिया में बन रहा है। उग्रसेन साहू ने कहा कि एक ओर सरकार और मंत्री की ओर से विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता की बात की जाती है, जीरो टॉलरेंस और जीरो कमीशन की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण अस्पताल के निर्माण को लेकर इस तरह के सवाल उठना गंभीर विषय है उन्होंने आरोप लगाया कि यदि निर्माण कार्य में वास्तव में नियमों की अनदेखी हो रही है तो यह न केवल सरकारी व्यवस्था पर सवाल है, बल्कि जनता के पैसों के इस्तेमाल से जुड़े गंभीर मुद्दे भी खड़े करता है। उग्रसेन साहू ने कहा कि 100 बिस्तर का अस्पताल क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए भविष्य की बड़ी स्वास्थ्य सुविधा है। अस्पताल एक बार बनता है और लंबे समय तक जनता के उपयोग में आता है। इसलिए इसके निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष तकनीकी टीम गठित कर पूरे निर्माण कार्य की जांच कराई जाए। निर्माण सामग्री, कॉलम की माप, नींव से लेकर अब तक हुए सभी कार्यों की जांच हो और यदि किसी स्तर पर अनियमितता मिलती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। अब सवाल यह है कि निर्माण को लेकर लगाए जा रहे इन गंभीर आरोपों पर प्रशासन कब तकनीकी जांच कराता है और जांच में क्या सच सामने आता है।

10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन, जिले के 3.89 लाख बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेन्डाजॉल की दवा

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में 10 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा। अभियान के तहत जिले के 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को कृमिनाशक दवा एल्बेन्डाजॉल खिलाई जाएगी। इसके लिए जिले में कुल 3,89,937 बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अंतर्गत जिले के शासकीय एवं निजी विद्यालयों, नवोदय विद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, आई.टी.आई., महाविद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को कृमिनाशक दवा का सेवन कराया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ मितानिन कार्यकर्ताओं की टीम गठित की गई है।

उम्र के अनुसार दी जाएगी एल्बेन्डाजॉल की निर्धारित मात्रा

अभियान के दौरान 1 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों को एल्बेन्डाजॉल की आधी गोली चूरा करके, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को एक पूरी गोली चूरा करके तथा 3 से 19 वर्ष के बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को एक पूरी गोली चबाकर खिलाई जाएगी। जिले को कृमि मुक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है। अभियान के तहत जिले के सभी शासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों को शामिल किया गया है। संबंधित विभागों के समन्वय से बच्चों तक कृमिनाशक दवा पहुंचाने और अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है।

कृमि संक्रमण से हो सकती है खून की कमी और कुपोषण

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. शरद कोहाड़े ने बताया कि बच्चों में कृमि संक्रमण के कारण कुपोषण, खून की कमी, मानसिक विकास में कमी तथा लगातार थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कृमिनाशक दवा के सेवन से पेट में मौजूद कृमियों को समाप्त करने में मदद मिलती है।

उन्होंने बताया कि कृमि संक्रमण से बचाव के लिए आसपास साफ-सफाई रखना, नाखून छोटे रखना, खुले में रखे भोजन का सेवन नहीं करना, खुले में शौच नहीं करना तथा शौच के बाद साबुन से हाथ धोना आवश्यक है। इसके अलावा फल एवं सब्जियों को स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धोकर एवं पकाकर खाने की सलाह दी गई है।

छूटे हुए बच्चों को 17 अगस्त को मॉप-अप दिवस पर दी जाएगी दवा

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने जिले के सभी पालकों एवं जनसामान्य से अपील की है कि 10 अगस्त 2026 को अपने समीपस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र, शासकीय अथवा निजी विद्यालय में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेन्डाजॉल की कृमिनाशक दवा का सेवन अवश्य कराएं। किसी कारणवश 10 अगस्त को दवा सेवन से छूटे बच्चों को 17 अगस्त 2026 को मॉप-अप दिवस के अवसर पर दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने जिलेवासियों से अभियान में सक्रिय सहभागिता कर जिले को कृमिमुक्त बनाने में सहयोग प्रदान करने की अपील की है।

सलिहा पुलिस की कार्रवाई, 45 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ कोचिया गिरफ्तार, भेजा जेल..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सलिहा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शराब कोचिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 45 लीटर हाथ भट्ठी से बनी कच्ची महुआ शराब, जिसकी कीमत करीब 4,500 रुपये बताई गई है, जब्त की है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश

पुलिस के अनुसार 7 अगस्त 2026 को थाना सलिहा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम आमाकछार निवासी बहादूर सारथी (44 वर्ष) अपने घर के पीछे निर्माणाधीन खुले मकान के पास अवैध महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुरेन्द्र मल्होत्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश दी। मौके पर आरोपी बहादूर सारथी को पकड़ लिया गया।तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से कुल 45 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी को मौके पर ही विधिवत गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर जिले में अवैध शराब, जुआ, सट्टा और मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी पुरेन्द्र मल्होत्रा, सहायक उपनिरीक्षक प्रकाश रजक, प्रधान आरक्षक नरेंद्र साहू, आरक्षक राजेश नारंग, चंद्रप्रकाश भारद्वाज, आनंद पुरेना सहित सलिहा थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

स्टाईपेंड को लेकर इंटर्न डॉक्टरों का तीसरे दिन भी हड़ताल जारी

रायगढ़/मूक पत्रिका

मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। स्टाइपेंड बढ़ाने की एकमात्र मांग को लेकर आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, लेकिन कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद डॉक्टरों ने नारेबाजी करते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया।मेडिकल कॉलेज के सामने करीब 62 इंटर्न डॉक्टर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में मिलने वाला स्टाइपेंड अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। लंबे समय से मांग करने के बावजूद सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया,

जिसके चलते उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। बुधवार को इंटर्न डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। बैठक में सकारात्मक आश्वासन तो मिला, लेकिन स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। इसके बाद डॉक्टरों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया। इंटर्न डॉक्टर राधेश्याम ने कहा कि बैठक में पूरी तरह सहमति नहीं बन सकी है। हालांकि सरकार की ओर से जल्द उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही कई वरिष्ठ और सेवानिवृत्त डॉक्टरों का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है।

जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह जैन के फर्जी जाति मामले में छानबीन समिति के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज

100 से अधिक ग्रामीणों व 50 से ज्यादा शपथ पत्रों के साथ प्रस्तुत हुए शिकायतकर्ता; जाति प्रमाण पत्र निरस्त होना तय

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी /मूक पत्रिका

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह जैन के कथित कूटचरित व फर्जी अनुसूचित जनजाति (गोंड) जाति प्रमाण पत्र के बहुचर्चित मामले में आज उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, नवा रायपुर के समक्ष अंतिम व निर्णायक सुनवाई संपन्न हुई।सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता विवेक सिंह के नेतृत्व में मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के 100 से अधिक ग्रामीण, सामाजिक प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिक स्वयं उपस्थित होकर कड़ा विरोध दर्ज कराने पहुँचे। समिति के समक्ष नम्रता सिंह जैन के दावे के विरोध में 50 से अधिक ग्रामीणों के हस्तक्षरित

एवं नोटरीकृत शपथ पत्र ऑन-रिकॉर्ड जमा कराए गए। प्रमुख सामाजिक दिग्गजों व प्रतिनिधियों की व्यापक उपस्थितिः सुनवाई के दौरान क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक व राजनैतिक दिग्गजों ने एक स्वर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का विरोध किया। उपस्थिति में मुख्य रूप से विवेक सिंह, पूर्व IG IPS डी. आर. आँचला, राज परिवार के लाल लक्ष्यमेंद्र शाह, संजीत ठाकुर, अवध चुरेंद्र, भुनेश कुमेटी, राजेंद्र नेताम , एम आर नायक , बालचंद्र कोरेटी , ब्लॉक उपाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज मंगलू तुलाबी, तिलक शोरी पूर्व लेखा संपरीक्षक ट्राइबल डिपार्टमेंट एवं गोंड व हल्बा आदिवासी समाज के सैकड़ों पदाधिकारी तथा सामाजिक लोग उपस्थित हुए। विवेक सिंह ने रखी अकाट्य विधिक दलीलें; समिति के सदस्यों ने जताई सहमतिःसुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता विवेक कुमार सिंह ने छानबीन समिति की पीठ के समक्ष पूर्व में भी 100 से अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी थी और आज भी 86 पृष्ठों के ठोस साक्ष्यों के साथ कड़ा विधिक पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने समिति के ध्यान में लाया कि अनावेदिका नम्रता सिंह जैन ने बचाव में केवल अपने पिता के सर्विस रिकॉर्ड और बर्थ सर्टिफिकेट ही जमा किए हैं, जो कि कानूनन किसी भी सूरत में उनकी 'जाति' का प्रमाण नहीं बन सकते। इसके विपरीत, सर्विस रिकॉर्ड से उनके पिता का मूल राज्य 'ओडिशा' होना सिद्ध होता है। साथ ही वर्ष 2018 की जिस ग्राम सभा मोहला के प्रस्ताव का सहारा लिया जा रहा है, उसका कोई एजेंडा या रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध ही नहीं है। बिलासपुर हाईकोर्ट के नवीनतम फैसलों (सुरेश डागला केस, 2024 एवं सुमन कुमारी केस, 2026) के तहत दूसरे राज्य से प्रवासित व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। विवेक सिंह द्वारा प्रस्तुत इन अकाट्य तर्कों से समिति के समस्त सदस्यों ने भी सहमति जताई। 12 से 15 दिनों में आएगा अंतिम फैसला; प्रमाण पत्र निरस्त होना तयः दोनों पक्षों के दस्तावेज जमा होने के बाद समिति द्वारा परस्पर प्रतियों के आदान-प्रदान और अगले 12 से 15 दिनों के भीतर अंतिम फैसला सुनाए जाने का मौखिक आदेश दिया गया है।

सुविधा के नाम पर स्मार्ट मीटर थोपकर जनता की जेब पर बोझ बढ़ा रही भाजपा सरकार, योजना तत्काल वापस हो : तरुण गोयल

रायगढ़ /मूक पत्रिका

युवा कांग्रेस के महामंत्री और रायगढ़ कांग्रेस शहर मध्य मंडल-2 के अध्यक्ष तरुण गोयल ने 'स्मार्ट मीटर' योजना को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से पूरे प्रदेश में बिजली बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। सरकार को जनता को महंगाई से राहत देनी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीब, मध्यमवर्गीय और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। तरुण गोयल ने कहा कि भयंकर महंगाई के इस दौर में आम परिवार पहले ही भारी आर्थिक दबाव से जूझ रहा है। रसोई का राशन, बच्चों की फीस, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन

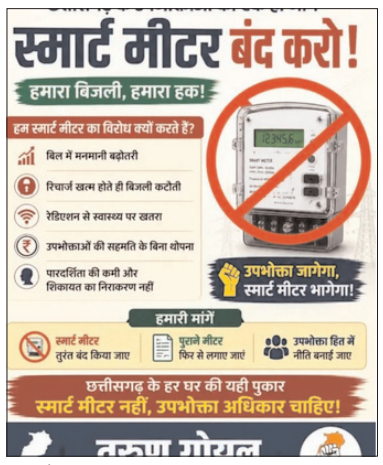

गया है। ऐसे समय में बिजली बिलों में अचानक बढ़ोतरी ने आम उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ा दी है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई परिवारों को सामान्य खपत के बावजूद कई गुना अधिक बिजली बिल आने की शिकायतें मिल रही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय लागू 'हाफ बिजली योजना' से लाखों परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलती थी। लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही जनता को मिलने वाली उस राहत को समाप्त कर दिया। अब स्मार्ट मीटर की आड़ में उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ रही है। सरकार को इस व्यवस्था पर तत्काल पुनर्विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख बिजली उत्पादक राज्यों में अग्रणी है। हमारे प्रदेश के पास कोयले और प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर भंडार है। जब छत्तीसगढ़ के संसाधनों से दूसरे राज्य रोशन हो रहे हैं, तो फिर यहां की जनता को ही महंगे बिजली बिलों का बोझ क्यों उठाना पड़े? प्रदेश के संसाधनों का पहला अधिकार और लाभ यहां की जनता को मिलना चाहिए। वहीं, तरुण अग्रवाल ने भाजपा सरकार से सवाल करते हुए कहा कि जिस स्मार्ट मीटर को सुविधा और पारदर्शिता के नाम पर लागू किया जा रहा है, उसके बाद ही जनता को बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायत क्यों करनी पड़ रही है? सरकार को अपनी जिद छोड़कर आम उपभोक्ताओं की परेशानी को समझते हुए इस योजना को वापस लेना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से दो-टूक मांग की कि स्मार्ट मीटर योजना को रद्द किया जाए, उपभोक्ताओं के घरों में पहले की तरह पारंपरिक मीटर लगाए जाएं और कांग्रेस सरकार के समय की 'हाफ बिजली योजना' को पुनः बहाल कर जनता को राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से खड़ी रही है। यदि सरकार ने आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम नहीं किया, तो कांग्रेस जनता की आवाज बनकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मजबूती से रखेगी।

जन्माष्टमी डिज्नीलैंड मेले का अनुमति आवेदन निरस्त, झूलों के किराए, गेट एंट्री फीस व सुरक्षा में गंभीर गड़बडियों पर कलेक्टर-एसडीएम की गाज

रायगढ़ /मूक पत्रिका

शहर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले बहुप्रतीक्षित 'डिज्नीलैंड मेले' को लेकर जिला प्रशासन ने अत्यंत कड़ा रुख अपनाया है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी, तकनीकी खामियों और आम जनता से मनमानी वसूली की तैयारियों को संज्ञान में लेते हुए रायगढ़ कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम द्वारा मेले के अनुमति आवेदन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। आयोजकों द्वारा मेले में लगाए जाने वाले विभिन्न झूलों की दरें अत्यधिक और अनियंत्रित तय की गई थीं। नियम के अनुसार प्रत्येक झूले के बाहर स्पष्ट रूप से स्वीकृत दर तालिका प्रदर्शित करना अनिवार्य होता है, लेकिन आयोजकों द्वारा दरों को पारदर्शी रखने की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई थी। मेले के मुख्य द्वार पर

प्रवेश के लिए 'गेट एंट्री टिकट' लागू करने की तैयारी थी। प्रवेश टिकटों के माध्यम से होने वाली आय और टिकट काउंटरों का कोई पारदर्शी लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिससे स्थानीय निकाय के राजस्व और कर नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई। मेले में जायंट व्हील, ब्रेक डांस, रोलर कोस्टर और टोरा-टोरा जैसे भारी-भरकम झूले स्थापित किए जा रहे थे। आयोजकों द्वारा इन झूलों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी (ढांचागत सुरक्षा) और लोक निर्माण विभाग या मेकेनिकल इंजीनियर से जारी वैध फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया गया था। इससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा होने की आशंका थी। जांच दल द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मेले में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन यंत्रों, पानी की व्यवस्था और आपातकालीन निकास का कोई ठोस ढांचा तैयार नहीं था। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, विद्युत सुरक्षा और फायर ब्रिगेड की अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही आयोजकों द्वारा स्थल पर झूलों और टिकट काउंटरों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, जो सीधे तौर पर नियमों और प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन है। प्रस्तावित मेला स्थल के आसपास पार्किंग की पर्याप्त और व्यवस्थित जगह न होने के कारण त्यौहार के दौरान शहर में गंभीर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होना तय था।रायगढ़ एसडीएम और कलेक्टर कार्यालय ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि आम नागरिकों और बच्चों की सुरक्षा तथा आर्थिक शोषण को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।आयोजकों को तुरंत प्रभाव से झूलों का ढांचा हटाने और परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस और नगर निगम की टीम को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुमति के यदि गेट एंट्री फीस लेने या झूलों का संचालन करने का प्रयास किया गया, तो संबंधितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जहाँ एक ओर मेले के निरस्त होने से त्यौहार का आकर्षण थोड़ा कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर झूलों के मनमाने किराए, गेट एंट्री वसूली और सुरक्षा संबंधी खतरों को समय रहते रोकने पर प्रबुद्ध नागरिकों ने प्रशासन के इस निर्णय की सराहना की है।

तारीख़ पे तारीख़...! चौहान समाज को आखिर कब मिलेगा अपना समाज भवन?

बरमकेला/मूक पत्रिका

घोषणाओं की गूंज तो कई बार सुनाई दी, लेकिन ज़मीनी हकीकत आज भी चौहान समाज के लिए सिर्फ़ इंतज़ार बनकर रह गई है। बरमकेला चौहान समाज में समाज भवन निर्माण को लेकर एक बार फिर भारी नाराज़गी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार, चौहान समाज के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े ने समाज भवन निर्माण के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपये देने की घोषणा की थी। समाज के लोगों का आरोप है कि घोषणा के बाद भी राशि स्वीकृत नहीं हुई। विरोध बढ़ने पर बाद में 10 लाख रुपये देने की बात कही गई, जिससे समाज को उम्मीद जगी कि अब भवन निर्माण का सपना पूरा होगा।लेकिन समाज के लोगों का कहना है कि हाल ही में विधायक निधि की कार्ययोजना तैयार होने के बावजूद चौहान समाज को फिर से

दरकिनार कर दिया गया। इससे समाज में गहरा असंतोष है। वरिष्ठजनों का आरोप है कि कई बार चर्चा और आग्रह के बाद भी केवल आश्वासन ही मिला। अप्रैल महीने में राशि जारी करने की बात कही गई है , लेकिन अभी विधायक मद कि राशि पर चौहान समाज पर ध्यान नहीं दिया गया है,इतना ही नहीं, खैरगढ़ी चौहान समाज भवन के लिए घोषित 3 लाख रुपये की राशि भी अब तक धरातल पर नहीं उतरने का आरोप लगाया जा रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि बार-बार घोषणाएं और तारीखें मिल रही हैं, लेकिन भवन निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब समाज के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है–क्या चौहान समाज के हिस्से में सिर्फ़ ÷तारीख़ पर तारीख़÷ ही आएगी, या कभी समाज भवन का सपना भी साकार होगा? समाज के लोगों का कहना है कि यदि लगातार उपेक्षा होती रही तो आने वाले समय में इस मुद्दे पर व्यापक आंदोलन की रणनीति भी बनाई जा सकती है। फिलहाल समाज में मायूसी के साथ-साथ गहरा आक्रोश व्याप्त है और लोग अपने जनप्रतिनिधियों से किए गए वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं।

वरिष्ठ समाजसेवी पुनीत चौहान ने कहा - ÷चौहान समाज के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में अघरिया भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक द्वारा चौहान समाज के भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की घोषणा की गई थी। सूत्रों के अनुसार विधायक मद की राशि दो-दो बार स्वीकृत होने के बावजूद आज तक चौहान समाज के भवन निर्माण हेतु उक्त राशि जारी नहीं की गई। इससे समाज के लोगों में गहरा आक्रोश और उपेक्षा की भावना व्याप्त है। समाज अपने अधिकार और सम्मान की अपेक्षा रखता है तथा घोषणा को शीघ्र अमल में लाने की मांग करता है।÷चौहान समाज जिलाध्यक्ष रामाधार चौहान ने कहा कि ÷भवन निर्माण के लिए सार्वजनिक मंच से घोषणा किए जाने के बावजूद उसे कार्ययोजना में शामिल नहीं किया जाना अत्यंत निंदनीय है। यह चौहान समाज की उपेक्षा को दर्शाता है। समाज चाहता है कि की गई घोषणा का सम्मान करते हुए भवन निर्माण के लिए तत्काल राशि स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ कराया जाए, ताकि समाज के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सके।÷

हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान राष्ट्र निर्माताओं के योगदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भव्य माध्यम बनेगा : अरुण साव

बस्तर संभाग में 500 से अधिक स्कूलों, प्रमुख चौराहों और सामुदायिक भवनों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाएगा : विजय शर्मा

उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव व विजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता में प्रदेशभर में आयोजित होने वाले 'हर घर तिरंगा' अभियान और 'तिरंगा यात्रा' की रूपरेखा साझा की

मूक पत्रिका/रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ÷हर घर तिरंगा÷ और ÷तिरंगा यात्रा÷ अभियान देशभक्ति की लहर जगाने, सामाजिक समरसता को मजबूत करने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राष्ट्र निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक भव्य और ऐतिहासिक माध्यम बनेगा। श्री साव ने शुक्रवार को यहाँ एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत महती पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए प्रदेशभर में आयोजित होने वाले 'हर घर तिरंगा' अभियान और 'तिरंगा यात्रा' की रूपरेखा साझा की।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि बस्तर के वे नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्र, जहाँ अब तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सका था, वहाँ इस वर्ष 15 अगस्त को तिरंगा लहराएगा। यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। श्री साव ने कहा कि वर्ष 2022 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति से जोड़ना, संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, सामाजिक समरसता तथा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को सुदृढ़ करना है। इस दौरान प्रदेश की सभी 450 से अधिक भाजपा मण्डल इकाइयों, बड़े गाँवों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों और विकासखण्ड मुख्यालयों में जन-जागरण हेतु तिरंगा यात्राएँ निकाली जाएंगीं। श्री साव ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए नगरीय निकायों, जिला पंचायतों और पार्टी पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक संपन्न हो चुकी है, साथ ही रायपुर शहर एवं ग्रामीण जिलों की बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं। आगामी 10 अगस्त को राजधानी के मरीन ड्राइव से तिरंगा यात्रा का ऐतिहासिक शुभारम्भ सुबह 10 बजे होगा। इस यात्रा में मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसद, विधायक, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स, पूर्व सैनिक, खिलाड़ी, स्वयंसेवी संस्थाएँ, धर्माचार्य और विभिन्न समाजों के विशिष्ट जन शामिल होंगे। यात्रा को यादगार बनाने के लिए लोग पारंपरिक वेशभूषा, वाद्य यंत्रों, घोड़ों और सवारियों के साथ शामिल होंगे।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सोशल मीडिया पर 'डिजिटल तिरंगा' अभियान की जानकारी देते हुए नागरिकों से अपील की है कि वे हर घर, दुकान, संस्थान और कार्यालय पर तिरंगा लहराएँ तथा अपनी फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करें। इससे पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि भारत अपनी आजादी का पर्व कितने गौरव और उल्लास के साथ मना रहा है!

राज्य निदेशक ए के सिंह ने एसबीआई आरसेटी सारंगढ़ का किया निरीक्षण

राज्य निदेशक के हाथों जूनियर ब्यूटी प्रैक्टिशनर, सब्जी उत्पादन एवं नर्सरी प्रबंधन के प्रशिक्षार्थियों को मिला प्रमाण-पत्र

मूक पत्रिका/. सारंगढ़-बिलाईगढ़, 7 अगस्त 2026/ केंद्र सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जिले के लीड बैंक के रूप में कार्यरत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आरसेटी केंद्र सारंगढ़ में छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के राज्य निदेशक (आरसेटी) ए के सिंह का आगमन हुआ। उन्होंने संस्थान का भ्रमण कर प्रशिक्षण गतिविधियों, कार्यालयीन व्यवस्थाओं एवं संस्थान की प्रगति का अवलोकन किया। इस अवसर पर जूनियर ब्यूटी प्रैक्टिशनर तथा सब्जी उत्पादन एवं नर्सरी प्रबंधन प्रशिक्षण के सफल प्रशिक्षार्थियों को राज्य निदेशक द्वारा प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

इस दौरान सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिले के आरसेटी निदेशक रिपुसूदन यदु, एलडीएम सी एस राजपूत के साथ संचालित एवं प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संस्थान के विकास तथा आरसेटी हेतु भूमि आवंटन, भवन निर्माण, स्टॉफ ट्रेनिंग की पूरी शेड्यूल आदि के संबंध में विस्तृत हुई। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने, स्वरोजगार स्थापित करने तथा उद्यमिता के माध्यम से सफल आजीविका अर्जित करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही, स्वरोजगार स्थापित कर चुके प्रशिक्षार्थियों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएँ दी। राज्य निदेशक ने संस्थान परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा प्रशिक्षार्थियों एवं आरसेटी सारंगढ़ का उत्साहवर्धन किया।

एसबीआई आरसेटी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के अपने उद्देश्य को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर फैकल्टी अतुल कुमार मिश्रा, विमला पटेल (ऑफिस असिस्टेंट), मधु यादव (ऑफिस असिस्टेंट), उमेश बरेठ एवं योगेश यादव आदि उपस्थित रहे।

दीपक चौधरी का सीएम हेल्पलाइन में डीजी पे मांग हुआ पूरा

कलेक्टर ने फोन पर की बात, आवेदक हुआ संतुष्ट

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 7 अगस्त 2026/कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने सीएम हेल्पलाइन में आए आवेदन का त्वरित निराकरण करते हुए उनके मांग पर आवश्यक प्रक्रिया कर उन्हें लाभान्वित किया है। जिले के आवेदक दीपक कुमार चौधरी ने सीएम हेल्पलाइन में अपने सेवा सेतु (सीएससी) आईडी में डीजी पे लाइट एक्टिव करने का मांग किया था। इससे आवेदक को सेवा सेतु (सीएससी) आईडी से डिजिटल माध्यम से रूपये लेन देन में सुविधा होगा। कलेक्टर ने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (ईडीएम) के माध्यम से आवेदक के सीएम हेल्पलाइन में किये मांग को पूरा किया और फोनकर इस संबंध में उन्हें जानकारी दी और अपने मांग के अनुरूप कार्य पूर्ण होने पर आवेदक ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कलेक्टर को धन्यवाद ज्ञापित किया है। सीएम हेल्पलाइन को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने समाधान के बाद भी स्वयं आवेदक दीपक कुमार चौधरी को फोन कर यह जानकारी ली कि उनकी समस्या का समाधान संतोषजनक ढंग से हुआ है या नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी परखा कि जिले में अधिकारी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर और प्रभावी ढंग से निराकरण कर रहे हैं या नहीं।

कट्टे की नोक पर शिक्षिका से लूट, ऑटो चालक पर भी हमला

दुर्ग। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रही एक शिक्षिका से कट्टे की नोक पर लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने ऑटो रुकवाकर पहले चालक को धमकाया, फिर शिक्षिका से छीनाझपटी कर पर्स लूट लिया। विरोध करने पर ऑटो चालक पर भी हमला कर दिया और उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, ग्राम जामगांव (एम) स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में व्याख्याता योगिता राज पुरोहित बुधवार शाम करीब 4 बजे स्कूल से छुट्टी के बाद ऑटो चालक राजेश धीवर के साथ मिलाईगढ़ स्थित अपने घर लौट रही थीं। दोनों अमेरी-बटंग-नरधी मार्ग से गुजर रहे थे। हाई स्कूल से करीब 400 मीटर पहले बाइक पर सवार दो बदमाशों ने ऑटो रुकवाया। एक आरोपी ने रास्ता पूछने का बहाना बनाया, जबकि दूसरे ने ऑटो चालक के कान पर कट्टानुमा हथियार अड़ा दिया। इसके बाद बदमाशों ने शिक्षिका से पर्स मांगा। मना करने पर छीनाझपटी कर पर्स छीन लिया। संघर्ष के दौरान ऑटो चालक राजेश धीवर के सिर पर भी चोट लगी।

बांदे में घर से गांजा बेचता अधेड़ गिरफ्तार, 2.10 लाख का गांजा व नगदी जब्त

दैनिक मूक पत्रिका / विक्रम ठाकुर/कांकेरः- उत्तर बस्तर कांकेर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे 'उजियरा अभियान' के तहत बांदे थाना पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक घर में दबिश देकर अवैध रूप से गांजा रखकर बिक्री कर रहे एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 4.300 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2.10 लाख रुपये बताई जा रही है, तथा बिक्री की नगद राशि 500 रुपये जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुरे के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी कुलदीप बंजारे के पर्यवेक्षण में जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 6 अगस्त 2026 को बांदे पुलिस को मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि ग्राम कुरेनार लोहारपारा निवासी सा लिक राम आंचला (50 वर्ष), पिता स्व. सोमा आंचला अपने घर में अवैध रूप से गांजा रखकर बेच रहा है। सूचना के आधार पर बांदे पुलिस और 94वीं बटालियन बीएसएफ बांदे की संयुक्त टीम ने ग्राम कुरेनार लोहारपारा स्थित संदेही के मकान में विधिवत छापेमारी की। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक पीले रंग की प्लास्टिक बोरी में छिपाकर रखा गया 4.300 किलोग्राम गांजा और बिक्री के 500 रुपये नगद बरामद हुए।

मामले में आरोपी सा लिक राम आंचला को गिरफ्तार कर बांदे थाने में अपराध क्रमांक 61/2026, धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक विवेचना की जा रही है। इस सफल कार्रवाई में बांदे थाना प्रभारी निरीक्षक रामचंद्र साहू, उप निरीक्षक विवेक वर्मा, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण बंजारे, प्रधान आरक्षक सूर्यदेव कुंजाम, आरक्षक यशवंत मंडावी, दिनेश नेताम, अमृत नेताम, मोहन दुग्गा तथा महिला आरक्षक हिरोन्दा दुग्गा का सराहनीय योगदान रहा।

भालू हमले के बाद ग्रामीणों का आंदोलन सफल, मरकटोला में बाउंड्री वॉल निर्माण को मिली मंजूरी

दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर/कांकेरः- कांकेर नरहरपुर विकासखण्ड लारगांव मरकाटोला भालू के हमले में दो ग्रामीणों की दर्दनाक मौत के बाद नरहरपुर विकासखण्ड के मरकाटोला गांव में ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। सुरक्षा व्यवस्था और स्कूल परिसर की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी समय धरने में बैठे ग्रामीणों का स्पष्ट कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर मौके पर निर्णय लेकर भूमि पूजन नहीं किया जाएगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाएंगे, तब तक वे धरना समाप्त नहीं करेंगे।

धरने की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग, वन विभाग , तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से चर्चा की। इसके बाद विधायक आशाराम नेताम भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने स्कूल की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल निर्माण, भालू की निगरानी और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी। ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने तत्काल बाउंड्री वॉल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की और मौके पर ही भूमि पूजन कराया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि सोमवार से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही वन विभाग ने क्षेत्र में भालू की लगातार निगरानी करने तथा ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वन अमले की तैनाती का आश्वासन दिया। काफी देर तक चले धरना प्रदर्शन और वार्ता के बाद जब मांगों पर तत्काल कार्रवाई हुई,भालू के हमले से हुई जनहानि पर परिजनों को 6-6 लाख रूपए की दी जाएगी मुआवजा राशि और तब ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी प्राथमिकता गांव के लोगों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा है, इसलिए वे लंबे समय से बाउंड्री वॉल और सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे।

गौरतलब है कि 5 अगस्त को मादा भालू के हमले में दो ग्रामीणों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल बन गया था, जिसके चलते ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा तत्काल निर्णय लिए जाने के बाद क्षेत्र में राहत का माहौल है।

सारंगढ़ जिला अस्पताल में 8 अगस्त को होगा पीएम सुरक्षित मातृत्व शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 7 अगस्त 2026/ जिला प्रशासन सारंगढ़- बिलाईगढ़ द्वारा मातृ-शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। इसी कड़ी में हर महीने की 9 और 24 तारीख को आयोजित होने वाला 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' का शिविर इस बार 9 अगस्त को रविवार होने के कारण 8 अगस्त यानी शनिवार को जिला चिकित्सालय सारंगढ़ में आयोजित किया जाएगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य हर गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य जांच मुहैया कराना है। इस अभियान के तहत जिला चिकित्सालय में कई सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाएंगी, जिसमें ?सम्पूर्ण स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा गर्भवती महिलाओं का गहन स्वास्थ्य परीक्षण, ?निःशुल्क सोनोग्राफी, गर्भस्थ शिशु की सेहत की सटीक निगरानी के लिए हाई-टेक सोनोग्राफी की मुफ्त सुविधा, खून, पेशाब समेत अन्य जरूरी पैथोलॉजी टेस्ट शामिल है। शिविर में आने वाली सभी गर्भवती माताओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक स्वल्पाहार की विशेष व्यवस्था की गई है।

अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने वाला फरार आरोपी भानुप्रतापपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार, भेजा गया जेल

दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर/कांकेरः उत्तर बस्तर कांकेर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने की कड़ी में बांदे थाना पुलिस ने युवती के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की विशेष टीम ने महाराष्ट्र निवासी आरोपी को भानुप्रतापपुर बस स्टैंड के पास से घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने बांदे थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि बांदे निवासी ब्रोजेन पाल और महाराष्ट्र के पुणे निवासी सागर काले ने मिलकर उसके अश्लील फोटो और वीडियो तैयार किए और उन्हें वायरल कर दिया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर बांदे पुलिस ने अपराध क्रमांक 50/2026, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(3), 77, 79 एवं आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुर्रे के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी कुलदीप बंजारे के पर्यवेक्षण में बांदे पुलिस की विशेष टीम गठित कर लगातार आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सटीक सूचना प्राप्त हुई कि फरार आरोपी सागर काले (29 वर्ष), निवासी मानमोड़ो (ताल्लुका जिंतुर, जिला परभणी, महाराष्ट्र) छत्तीसगढ़ पहुंचा है और रायपर से पखांजर की तरफ जा रहा है। सूचना मिलते ही बांदे पुलिस की टीम तत्काल रवाना हुई और भानुप्रतापपुर बस स्टैंड पर घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी सागर काले ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी जब्त कर लिया है। इसके पश्चात आरोपी को पखांजूर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर उसे कांकेर जेल भेज दिया गया। इस संपूर्ण कार्रवाई में बांदे थाना प्रभारी निरीक्षक रामचंद्र साहू, उप निरीक्षक विवेक वर्मा, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण बंजारे, प्रधान आरक्षक सूर्यदेव कुंजाम, आरक्षक यशवंत मंडावी, दिनेश नेताम, अमृत नेताम और मोहन दुग्गा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एवीएफओ नरोत्तम समरथ एकतरफा रिलीव, वर्तमान पदस्थापना से वेतन आहरण तत्काल प्रभाव से बंद, अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव तलब

मंत्री के आदेश को 40 दिन दबाए रखा, अब उपसंचालक पर कार्रवाई की तैयारी

मूक पत्रिका/बीजापुर/आशीष पदमवार। पशुपालन विभाग में मंत्री के आदेश की अनदेखी अधिकारियों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। विभागीय मंत्री रामविचार नेताम के 26 जून के स्पष्ट निर्देश के बावजूद सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (एवीएफओ) नरोत्तम समरथ को करीब 40 दिन तक कार्यमुक्त नहीं किया गया। मामला शासन तक पहुंचने के बाद सचिव ने सीधे हस्तक्षेप करते हुए नरोत्तम समरथ को तत्काल प्रभाव से एकतरफा कार्यमुक्त करने, उनके वर्तमान पदस्थापना स्थल से वेतन आहरण रोकने तथा आदेश का पालन नहीं करने वाले उपसंचालक डॉ. राजीव शर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव संचालक, पशुपालन विभाग से मांग लिया है।

विभागीय दस्तावेजों के अनुसार मंत्री ने 26 जून को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि एवीएफओ नरोत्तम समरथ को तत्काल रिलीव किया जाए। साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख था कि निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधित उपसंचालक जिम्मेदार होंगे। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ और समरथ पूर्ववत कार्य करते रहे।

जानकारी के अनुसार नरोत्तम समरथ लंबे समय से उपसंचालक कार्यालय से संबद्ध थे। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2016 में उनका स्वयं के व्यय पर बस्तर जिले के बकावंड पशु औषधालय में स्थानांतरण हुआ था। आरोप है कि स्थानांतरण के बाद भी उन्होंने नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया और उपसंचालक कार्यालय में ही संलग्न रहे। इसी दौरान उनके खिलाफ अनियमितताओं और शिकायतों के कई मामले भी सामने आए, जिनकी जानकारी विभागीय मंत्री तक पहुंची।

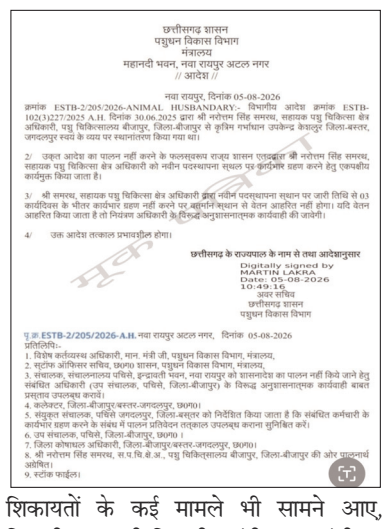

छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 05-08-2026

क्रमांक ESTB-2/205/2026-ANIMAL HUSBANDARY:- विभागीय आदेश क्रमांक ESTB-102(3)227/2025 A.H. दिनांक 30.06.2025 द्वारा श्री नरोत्तम सिंह समरथ, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, पशु चिकित्सालय बीजापुर, जिला-बीजापुर से कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र केशलुर जिला-बस्तर, जगदलपुर स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण किया गया था।

2/ उक्त आदेश का पालन नहीं करने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा श्री नरोत्तम सिंह समरथ, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु एकपक्षीय कार्यमुक्त किया जाता है।

3/ श्री समरथ, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर जारी तिथि से 03 कार्यदिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर वर्तमान स्थान से वेतन आहरित नहीं होगा। यदि वेतन आहरित किया जाता है तो नियंत्रण अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

4/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
Digitally signed by
MARTIN LAKRA
Date: 05-08-2026
10:49:16
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

पृ.क्र.ESTB-2/205/2026-A.H. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 05-08-2026
प्रतिलिपिः-
1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्री जी, पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय,
2. स्टॉफ ऑफिसर सचिव, छ0ग0 शासन, पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय,
3. संचालक, संचालनालय पचिसे, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को शासनादेश का पालन नहीं किये जाने हेतु संबंधित अधिकारी (उप संचालक, पचिसे, जिला-बीजापुर) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत प्रस्ताव उपलब्ध करावें।
4. कलेक्टर, जिला-बीजापुर/बस्तर-जगदलपुर, छ0ग0।
5. संयुक्त संचालक, पचिसे जगदलपुर, जिला-बस्तर को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में पालन प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. उप संचालक, पचिसे, जिला-बीजापुर, छ0ग0 ।
7. जिला कोषाधल अधिकारी, जिला-बीजापुर/बस्तर-जगदलपुर, छ0ग0।
8. श्री नरोत्तम सिंह समरथ, स.प.चि.क्षे.अ., पशु चिकित्सालय बीजापुर, जिला-बीजापुर की ओर पालनार्थ अग्रेषित।
9. स्टॉक फाईल।

मामले के तूल पकड़ने के बाद सचिव पशुपालन विभाग ने आदेश जारी कर समरथ को तत्काल प्रभाव से एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि जारी होने की तिथि से उनके वर्तमान पदस्थापना स्थल से वेतन आहरण तत्काल रोक दिया जाए।

वहीं मंत्री के आदेश का समय पर पालन नहीं करने और शासन की छवि धूमिल होने के कारण उपसंचालक डॉ. राजीव शर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव संचालक, पशुपालन विभाग से मांगा गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

घटनाक्रम एक नजर में

- मंत्री ने 26 जून को तत्काल रिलीव करने के दिए थे निर्देश।
- करीब 40 दिन तक आदेश का पालन नहीं हुआ।
- शासन ने एवीएफओ नरोत्तम समरथ को एकतरफा कार्यमुक्त किया।
- वर्तमान पदस्थापना स्थल से वेतन आहरण पर तत्काल रोक।
- उपसंचालक डॉ. राजीव शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव तलब।

क्या है मामला

विभागीय दस्तावेजों के अनुसार एवीएफओ नरोत्तम समरथ लंबे समय से उपसंचालक कार्यालय में संलग्न थे। आरोप है कि स्थानांतरण होने के बावजूद उन्होंने नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। शिकायतें मिलने पर विभागीय मंत्री ने तत्काल रिलीव करने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण अब शासन ने सीधे हस्तक्षेप करते हुए कड़े प्रशासनिक कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर बेमेतरा का गौरव बढ़ाने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं एवं पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने प्रिंस सिंह और आशीष पाटिल को दी शुभकामनाएं

बेमेतरा/मूक पत्रिका

राष्ट्रीय स्तर की सॉफ्टबाल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बेमेतरा जिले का नाम रोशन करने वाले दो प्रतिभावान खिलाड़ियों प्रिंस सिंह एवं आशीष पाटिल का बीते शुक्रवार को कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं एवं पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने सम्मान किया। दोनों खिलाड़ियों ने सॉफ्टबाल खेल में छत्तीसगढ़ राज्य की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर नेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि के आधार पर राज्य शासन द्वारा उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है।सम्मान के दौरान कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं एवं पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने दोनों खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि जिले के युवा खिलाड़ियों द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। खिलाड़ियों की सफलता अन्य युवाओं को भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित करती है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए गए खिलाड़ियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप शासकीय सेवा में अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इससे खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ युवाओं में खेलों के प्रति रुचि एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा मिलता है।

प्रिंस सिंह ने 29 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीते 26 पदक-ग्राम जेवरा निवासी प्रिंस सिंह ने सॉफ्टबाल खेल में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने अब तक 29 बार नेशनल एवं फेडरेशन कप प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 26 पदक अपने नाम किए हैं। निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के चलते प्रिंस सिंह ने जिले एवं छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है।

आशीष पाटिल ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीते 5 पदक-इसी तरह ग्राम जेवरा के ही आशीष पाटिल ने भी सॉफ्टबाल खेल में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 7 बार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर 5 पदक अर्जित किए हैं। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित सम्मान अवसर पर दोनों उत्कृष्ट खिलाड़ियों के साथ शाला प्रबंधन समिति के सदस्य प्रबल सिंह, प्राचार्य विनोद चौहान, व्यायाम शिक्षक मृत्युंजय शर्मा एवं नोवेन्द्र साहू उपस्थित रहे। अधिकारियों एवं उपस्थितजनों ने दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जिले के इन खिलाड़ियों की उपलब्धि से बेमेतरा में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के प्रयासों को भी नई प्रेरणा मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर शासकीय सेवा के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में चयनित होना जिले के अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए भी एक प्रेरणादायी उदाहरण है।

मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय बनाने के नाम पर सरकारी जमीन बर्बाद

एक ओर बनाने के बजाय रोड के दोनों तरफकी जमीन पर निर्माण, पुसौर जनपद पंचायत में बिना स्पॉट देखे मंजूरी

रायगढ़/मूक पत्रिका

गांवों में मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय निर्माण के नाम पर मनमानी जगह पर काम करवाया जा रहा है। बिना प्लानिंग के सरपंच का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सरकारी जमीनें खराब की जा रही हैं। रोड के एक ओर पर्याप्त भूमि होने के बावजूद पुसौर के गुड्डु में दोनों तरफ की जमीन पर निर्माण किया गया है। प्रत्येक गांव में अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय बनाए जा रहे हैं। पुसौर के गुड्डु में भी इसकी मंजूरी मिली थी। सरपंच ने मेन रोड किनारे दोनों ओर की सरकारी जमीन पर निर्माण का प्रस्ताव भेज दिया। जनपद पंचायत पुसौर में भी इसे स्वीकृति दे दी गई। दरअसल रोड के एक ओर पर्याप्त शासकीय जमीन थी। इस पर मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय दोनों का निर्माण हो सकता था। दूसरी ओर की भूमि को किसी अन्य कार्य में उपयोग किया जा सकता था। मिली जानकारी के मुताबिक इस बारे में सरपंच और जनपद सीईओ से भी आपत्ति की गई थी, लेकिन निर्माण नहीं रोका गया।

रोड से सटाकर निर्माण

गांवों के बीच पहुंच मार्ग संकरे होते जा रहे हैं। जिस जगह मुक्तिधाम का निर्माण हुआ है, वहां भी पीछे जमीन होने के बावजूद रोड से सटाकर निर्माण किया गया। इस वजह से रोड चौड़ीकरण नहीं हो सकेगा। बताया जा रहा है कि पीछे की खाली जमीन पर अतिक्रमण करने की योजना है। इसीलिए दोनों ओर की भूमि को उपयोग किया गया।

ग्रामीण एवं नगरी क्षेत्रों में सड़कों पर बैठे मवेशी बन रहे दुर्घटनाओं का कारण

बलौदाबाजार/मूक पत्रिका

ताराचंद कठोत्रे । ग्रामीण अंचलों एवं शहरों की मुख्य सड़कों पर आवारा मवेशियों के बैठने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सड़क के बीचों-बीच बैठे मवेशियों के कारण वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । जिससे हर दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। विशेषकर रात्रि के समय और बारिश के मौसम में सड़क पर बैठे मवेशी आसानी से दिखाई नहीं देते, जिसके कारण दोपहिया एवं चारपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। कई स्थानों पर छोटे-बड़े हादसे भी हो चुके हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन एवं नगर पंचायत से मांग की है कि आवारा मवेशियों के उचित प्रबंधन की व्यवस्था व गले मे रेडिएम की जाए तथा उन्हें गौशालाओं या सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए ताकि यातायात सुचारु रूप से संचालित हो सके और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में विकास कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए हुई गहन चर्चा, बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर

जगदलपुर/मूक पत्रिका

जगदलपुर से स्थित ?जिला पंचायत बस्तर के सभागार में आयोजित सामान्य सभा की बैठक जिले के सर्वांगीण विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन की दिशा में गहन चर्चा के साथ ही बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप की अध्यक्षता और नवपदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय खन्ना की उपस्थिति में संपन्न हुई इस बैठक में जिले की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई दूरगामी निर्णय लिए गए

?बैठक की शुरुआत करते हुए अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत किया और इस बात पर विशेष बल दिया कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के मध्य सशक्त समन्वय होना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सामान्य सभा में सदस्यों द्वारा उठाई गई जन-समस्याओं का समाधान एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि एक ही मुद्दे पर बार-बार चर्चा करने की स्थिति न बने। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को मैदानी जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत करवाए गए समस्याओं को गंभीरता से लेने तथा बारिश के मौसम के दृष्टिगत स्कूल भवनों के सुधार सहित स्कूलों, आँगनबाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता एवं साफ़ सफ़ाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग को खाद-बीज की समय पर उपलब्धता तथा विद्युत व्यवस्था का सुचारू रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश देने के साथ ही एजेंडा की जानकारी कम से कम तीन दिन पूर्व उपलब्ध कराने और विभिन्न समितियों की मासिक बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित करने की बात कही। इसी क्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी ने भी प्रशासनिक जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना सभी का पहला कर्तव्य है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी ये बैठकें नियमित होंगी और आपसी समन्वय से क्षेत्र की समस्याओं का त्वरित समाधान निकाला जा सकेगा। बैठक में नवपदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय खन्ना का आत्मीय स्वागत किया गया, जिन्होंने बस्तर के विकास के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत किया। जनप्रतिनिधियों के मैदानी अनुभवों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनके अनुभवों से सीखकर बेहतर समन्वय के साथ परिणाममूलक कार्य करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। सीईओ जिला पंचायत श्री खन्ना ने मनरेगा और 'पीएम जनमन' जैसी योजनाओं को जिले के विकास हेतु सशक्त माध्यम बताते हुए जानकारी दी कि जिले में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग दोगुना बजट खर्च करने का विस्तृत स्पेंडिंग प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों का उदाहरण देते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्लान कर पक्के स्कूल भवन, आंगनाड़ी केंद्र, टॉयलेट, शेड और पीडीएस दुकानों जैसी टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि आजीविका संवर्धन, स्कूल ड्रॉप-आउट रोकने, कुपोषण मुक्ति और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसे सामाजिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शहीद जवानों के परिजनों से भेंट कर तिरंगा भेंट करते हुए किया सम्मान

देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने किया सम्मान, रिटायर्ड जवानों को तिरंगा ध्वज भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने भेंट किया

जगदलपुर/मूक पत्रिका

भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिला बस्तर के सदस्यों ने राष्ट्र की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीद जवानों के परिजनों एवम रिटायर्ड जवानों से उनके निवास पर पहुँचकर आत्मीय भेंट की तथा उन्हें तिरंगा ध्वज भेंट कर सम्मानित किया।भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात शहीद जवान देवेंद्र कुमार के निवास ग्राम धोबिगुड़ा, रिटायर्ड आर्मी जवान ललित जोशी सहित अन्य से भेंट कर उन्हें ससम्मान तिरंगा ध्वज भेंट किया है। इस अवसर पर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभिलाष यादव ने कहा कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों का बलिदान सदैव राष्ट्र के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा।

उनके परिवारों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। शहीदों के परिजनों के त्याग, धैर्य और देशभक्ति को नमन करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।जिला उपाध्यक्ष आनंद झा ने कहा कि तिरंगा केवल भारत की आन-बान और शान का प्रतीक नहीं, बल्कि उन वीर सपूतों के सर्वोच्च बलिदान का भी प्रतीक है, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। देश की रक्षा में तैनात सभी वीर जवानों को हम सलाम करते है। युवा मोर्चा सदैव राष्ट्रभक्ति और समाजसेवा के ऐसे कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा।इस अवसर पर भारतीय जनता युवा जिलाध्यक्ष अभिलाष यादव, उपाध्यक्ष आनंद झा, विकास पात्रो, सोमप्रकाश जोशी,परेश टाटी ,प्राचीन तिवारी,जशवंत जोशी,दीपक पांडे, तनिष्क सिंह, सहित युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख अब 14 अगस्त, 31 जुलाई की समय-सीमा बढ़ी, किसानों को मिला अतिरिक्त मौका – धान सिंचित के लिए ?1,320 और असिंचित के लिए 946 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित

बेमेतरा/मूक पत्रिका

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 में अधिसूचित फसलों का फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि अब 14 अगस्त 2026 कर दी गई है। पूर्व में फसल बीमा पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 14 अगस्त किया गया है। इससे ऐसे किसानों को अतिरिक्त अवसर मिला है, जो किसी कारणवश निर्धारित समय-सीमा में अपनी फसल का बीमा नहीं करा पाए थे। जिले के किसान अब 14 अगस्त तक अपने निकटतम बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र (ष्ट्रस्ष्ट) सहित निर्धारित माध्यमों से फसल बीमा करा सकते हैं।

किसानों को देना होगा केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान को बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है। शेष प्रीमियम राशि का वहन केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा किया जाता है। बेमेतरा जिले में खरीफ फसल के लिए कृषक प्रीमियम राशि धान सिंचित के लिए ?1,320 प्रति हेक्टेयर तथा धान असिंचित के लिए ?946 प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है।इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य जोखिमों के कारण फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि फसल खराब होने की स्थिति में किसानों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके।

इन परिस्थितियों में मिलेगा फसल बीमा का लाभ-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में विभिन्न परिस्थितियों में फसल को होने वाले नुकसान को बीमा सुरक्षा के दायरे में लिया गया है। इनमें अधिसूचित क्षेत्र में बुवाई न हो पाना, स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को नुकसान, फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपज में कमी जैसी परिस्थितियां शामिल हैं। इसके अलावा फसल कटाई के बाद निर्धारित अवधि के भीतर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के लिए भी प्रावधान है। फसल कटाई के बाद 14 दिनों की निर्धारित अवधि में ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा जैसी घटनाओं से फसल को नुकसान होने पर बीमा एवं क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

फसल को नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर दें सूचना-किसानों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि स्थानीय प्राकृतिक आपदा अथवा फसल कटाई के बाद नुकसान होने की स्थिति में इसकी सूचना 72 घंटे के भीतर संबंधित विभाग को देना आवश्यक है। किसान नुकसान की सूचना कृषि विभाग, राजस्व विभाग, कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447 अथवा व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 70655-14447 के माध्यम से दे सकते हैं। समय पर नुकसान की सूचना मिलने से संबंधित प्रक्रिया के तहत फसल क्षति का आकलन एवं आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। इसलिए किसान प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने की स्थिति में बिना देरी किए इसकी सूचना संबंधित माध्यम से देना सुनिश्चित करें।

ऋणी और अऋणी दोनों किसान करा सकते हैं बीमा-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान ले सकते हैं। अऋणी किसानों को फसल बीमा कराने के लिए आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इनमें आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका/बी-1, बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र अथवा स्वघोषणा पत्र तथा मोबाइल नंबर शामिल हैं। वहीं बटाईदार, काश्तकार एवं साझेदार किसानों को फसल साझा अथवा काश्तकार संबंधी घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

जिले में सरकारी कार्यालयों से प्रीपेड बिजली व्यवस्था की शुरुआत : आयुष और परिवहन विभाग ने कराया पहला रिचार्ज

पारदर्शिता और ऊर्जा संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

बलौदाबाजार/मूक पत्रिका

ताराचंद कठोत्रे ।राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में विद्युत व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। बिजली विभाग द्वारा शासकीय कार्यालयों में डिजिटल प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने और प्रीपेड बिजली भुगतान प्रणाली की शुरुआत कर दी गई है।इसी कड़ी में आयुष विभाग अंतर्गत शासकीय आयुर्वेद अस्पताल कसडोल और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए अपने-अपने बिजली खातों को अग्रिम (प्रीपेड) रिचार्ज कराकर इस नई व्यवस्था का विधिवत शुभारंभ किया है।कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के जिला कार्यालय में प्रीपेड बिलिंग हेतु स्मार्ट मीटर लगाने की कार्यवाही तेज कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्री -पेड रिचार्ज की प्रक्रियानुसार तिमाही आधार पर तय की गई है।प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त विद्युत् कनेक्शन की प्री पेड की प्रक्रिया उसे केंद्रीयकृत या जिलेवार अथवा डीडीओ वार रखना है।रिचार्ज सम्बंधित विस्तृत जानकारी मोर बिजली एप एवं सीएसपीडीसीएल की वेब साईट पर उपलब्ध रहेगी।किसी भी ग्रुप के रिचार्ज राशि का तीन महीने के समाप्ति के निकट पहुंचने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करने हेतु एसएमएस या वाहट्सएप द्वारा अनुस्मरण प्रेषित किया किया जायेगा। विभागों द्वारा प्रीपेड रिचार्ज कराने से जिले में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। आयुष एवं पशुपालन विभाग की यह पहल अन्य विभागों और आम उपभोक्ताओं को भी डिजिटल प्रीपेड व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। पारदर्शिता और ऊर्जा संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा-?बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस प्रणाली के लागू होने से न केवल बिजली बिलों के समय पर भुगतान की समस्या खत्म होगी, बल्कि विभाग अपने बिजली खर्च और खपत की रियल-टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे।रिचार्ज की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और बहुत सरल है जिससे कागजी कार्रवाई में लगने वाले समय की बचत होगी।?सटीक खपत प्रबंधन प्रीपेड व्यवस्था से शासकीय विभागों को अपनी बजट योजना और बिजली की खपत को नियंत्रित रखने में आसानी होगी।

लावारिश कुत्ते को भगाने की बात पर विवाद, पुरानी रंजिश में युवक की हत्या; चार आरोपी गिरफ्तार

मूक पत्रिका/बेमेतरा - जिला बेमेतरा के थाना साजा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरतरा में मामूली विवाद और पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। साजा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बोरतरा निवासी श्रीमती ललिता प्रजापति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 6 अगस्त की सुबह वह अपने पति ओमप्रकाश प्रजापति के साथ खेत जा रही थीं। इसी दौरान एक लावारिश कुत्ता उनके पीछे आ रहा था, जिसे ओमप्रकाश ने भगाया। इस बात को गलत तरीके से समझते हुए गांव के शिवकुमार श्रीवास, सोमनाथ उर्फ छोटू श्रीवास, दीपक श्रीवास और रोशन श्रीवास ने विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि पुरानी रंजिश के कारण चारों आरोपियों ने एक राय होकर डंडे और पत्थरों से ओमप्रकाश प्रजापति पर हमला कर दिया। हमले में ओमप्रकाश के सिर और पसलियों में गंभीर चोटें आईं, जबकि बीच-बचाव करने के दौरान उनकी पत्नी भी घायल हो गईं। घायल ओमप्रकाश को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा और बाद में जिला अस्पताल बेमेतरा ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी बेरला श्रीमती रूचि वर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी साजा निरीक्षक जनक साहू पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम की भी सहायता ली गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों परिवारों के बीच पहले से आपसी विवाद और मनमुटाव चल रहा था। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडे और पत्थर सहित अन्य साक्ष्य जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी शिवकुमार श्रीवास (55 वर्ष), रोशन श्रीवास (27 वर्ष), दीपक श्रीवास (25 वर्ष) तथा सोमनाथ उर्फ छोटू श्रीवास (23 वर्ष), सभी निवासी ग्राम बोरतरा, थाना साजा, को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।